वैक्सीन से आस ?

कोरोना काल में बहुत-सी चीजें बदल गई हैं। कोरोना काल से पहले हम जो सामान्य जीवन जी रहे थे, जानलेवा कोरोना वायरस की वैक्सीन आने तक अब उस दौर में लौटना संभव नहीं दिख रहा है। अब साइबर दुनिया सभी के जीवन का अभिन्न बन गया है। यह अब 'न्यू नॉर्मल' है। कोरोना के चलते दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। दो गज की दूरी तथा मुंह पर मास्क पहनना मानव जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बन गया है। कोरोना

प्रोटॉकॉल के तहत इस तरह के बहुत से बदलाव हैं, जिनके साथ जीना ही अब न्यू नॉर्मल है। प्रचलन में आया यह 'न्यू नॉर्मल' शब्द पुराना हो सकता है, लेकिन उसके तहत परिभाषित मानव जीवनशैली व व्यवहार नये हैं। इसी जीवनशैली में यह दुनिया वर्चुअल दुनिया में बदल गई है।

यह खुशखबरी है कि भारत कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने की ओर कामयाबी के साथ बढ़ रहा है। कोवैक्सीन नाम की जो दवा भारत बना रहा है, उसे जानवरों में कारगर पाया गया है और अब मनुष्यों में भी परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब भी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन तब भारत में कोरोना का प्रकोप ज्यादा नहीं था। भारत में 48 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 78 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है, इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि देश अपनी विशाल आबादी के लिए खुद वैक्सीन विकसित करे। किसी भी अन्य देश की तुलना में आज भारत में वैक्सीन की सर्वाधिक जरूरत है। हमसे ज्यादा आबादी वाले चीन ने कोरोना पर शिकंजा कस लिया है, पर हम तेजी से सर्वाधिक पीड़ित देश होने की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा पीड़ित होने के दाग को हम केवल वैक्सीन विकसित करके ही धो सकते हैं।

अब दिल्ली स्थित एम्स में कोवैक्सिन का फेज 2 ट्रायल शुरू हो चुका है। एक वॉलंटीयर को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। सफलता मिल गई, तो 750 इंसानों पर उसे आजमाया जाएगा और उसके बाद फेज 3 ट्रायल में हजारों लोगों पर परीक्षण होगा। इस पूरी कवायद में कम से कम तीन महीने का वक्त लगेगा और सब कुछ ठीक रहा, तो अगले साल की पहली तिमाही में भारत अपने वैक्सीन का निर्माण कर लेगा। ध्यान रहे, भारत में वैक्सीन की खोज में अभी सात कंपनियां लगी हैं, भारत बायोटेक, कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट, मिनवेक्स, इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स और बायोलॉजिकल ई। सब अलग-अलग वैक्सीन पर काम कर रही हैं। अभी तक रूस में विकसित वैक्सीन स्पुतनिक-वी को स्थानीय स्तर पर मंजूरी मिली है, लेकिन यह वैक्सीन फेज 3 ट्रायल से नहीं गुजरी है, इसलिए विवाद बना हुआ है। खैर, भारत में जो भी दवा आए, पूरी तरह से परखने के बाद आए। इस खोज में धन या संसाधन की कतई कमी नहीं आने देनी चाहिए। जो भी वैज्ञानिक और आम लोग इस परीक्षण में भागीदारी का जोखिम उठा रहे हैं, पूरी मानवता उनकी सदा आभारी रहेगी।

वैक्सीन निर्माण में लगे इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों की तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने अप्रैल महीने से ही वैक्सीन खोज अभियान छेड़ रखा है और 29 जून को ही वैक्सीन बना ली थी। इसी के आधार पर कभी यह घोषणा भी हो गई थी कि भारत में 15 अगस्त तक वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन किसी भी वैक्सीन को हर तरह से सुरक्षित सिद्ध करने में समय तो लगता ही है। बहरहाल, खास यह कि कोवैक्सीन कोरोना स्ट्रेन से ही तैयार की गई है और शरीर में जाने के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार करती है। भारत बायोटेक के वैज्ञानिक इसी वैक्सीन की मदद से बंदरों में एंटीबॉडी विकसित करने में कामयाब रहे हैं। 20-20 बंदरों के चार समूहों पर अलग-अलग जगह वैक्सीन को आजमाया गया है। 14 दिनों के अंतराल पर बंदरों को दो बार वैक्सीन दी गई और उसके बाद उन्हें कोरोना संक्रमित करने की कोशिश हुई, मगर वैक्सीन की वजह से बंदरों के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो गई थी और उनमें निमोनिया या कोरोना लक्षण नहीं उभरे।

भरत सिंह चौहान
संपादक

यह खुशखबरी है कि भारत कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने की ओर कामयाबी के साथ बढ़ रहा है। कोवैक्सीन नाम की जो दवा भारत बना रहा है, उसे जानवरों में कारगर पाया गया है और अब मनुष्यों में भी परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, तब भी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन तब भारत में कोरोना का प्रकोप ज्यादा नहीं था। भारत में 48 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं

पुष्पांजली टुडे

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष 06, अंक 08, अक्टूबर 2020,

मूल्य 30 रु, पृष्ठ 44

संरक्षक	बहादुर सिंह चौहान
संपादक	भरत सिंह चौहान
प्रबंध संपादक	शैलेश सिंह कुशवाह
उपसंपादक	अरविंद सिंह नरवरिया
	अर्पित गुप्ता
	प्रदीप नागेन्द्र सिकरवार
	शशिभूषण चौहान (मप्र)
कानूनी सलाहकार	एड. आर. के. जोशी
ऑल इंडिया रिपोर्टर	अन्जू भरमोरिया
राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी	आर एस रजक

ब्यूरो प्रमुख

पंकज त्रिपाठी	:	मध्य प्रदेश
राजानल शर्मा	:	छत्तीसगढ़
नरेन्द्र शर्मा	:	हरियाणा
अभिषेक मिश्रा	:	हिमाचल प्रदेश
अमित कुमार	:	जम्मू-कश्मीर (यूटी)
अमन राय	:	बर्दवान पश्चिम बंगाल
नारायण लाल	:	बेंगलुरु
दीपक रलहन	:	पंजाब
नैनाराम सिरवी	:	पाली, राजस्थान
संदीप प्रधान	:	ग्वालियर संभाग
केवल राम मालवीय	:	इंदौर
राजा दुबे	:	सीहोर
केशव प्रसाद शर्मा	:	मुरैना
राजेश लोधी	:	रायसेन
रीतेश कटरे	:	बालाघाट
सुरजीत राजावत	:	ग्वालियर
बरखा श्रीवास्तव	:	ग्वालियर
हरिनिवास दुबे	:	मथुरा (उत्तर प्रदेश)
सोनू कुमार माथुर	:	एटा, (उत्तर प्रदेश)
प्रवेन्द्र सिंह	:	आगरा (उत्तर प्रदेश)
अरविंद प्रताप सिंह	:	कन्नौज (उत्तर प्रदेश)
रूपसिंह	:	इटावा, (उत्तर प्रदेश)
किरण राठौर	:	औरैया, (उत्तर प्रदेश)
अरूण शुक्ला	:	भिण्ड
मोहन मांझी	:	गोहद
अमित शर्मा	:	ग्वालियर

कार्यालय

ए-ब्लॉक 404 भाऊसाहब पोतनीस, इन्क्लेव, मुरार रोड गोले का मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश

संपर्क: 8269307478, 7999246560

www.pushpanjalitoday.com, Email-pushpanjalitoday@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक भारत सिंह चौहान। कंचन प्रिंटिंग प्रेस निम्बालकर का बाड़ा, तेजी की बजरिया नियर पी.एंड.एन. बैंक नया बाजार लश्कर ग्वालियर म.प्र. से मुद्रित तथा दीपू इलेक्ट्रोनिक्स हनुमान मंदिर के पास, गोवर्धन कॉलोनी भिण्ड रोड, गोला का मंदिर जिला ग्वालियर म.प्र. से प्रकाशित। संपादक भारत सिंह चौहान। (समाचारों के चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार) दूरभाष 8269307478

इस अंक में

03

पुष्पांजली टुडे टीम

अनिल पाराशर	: मध्य प्रदेश क्राइम रिपोर्टर
कुसुम भदौरिया	: मध्य प्रदेश
महेन्द्र शर्मा	: चम्बल संभाग
गौरव शर्मा	: चम्बल संभाग
योगेश शर्मा	: चम्बल संभाग
राधा तोमर	: अम्बाह
जितेन्द्र सिंह	: खेरागढ़, आगरा
भीमसेन तोमर	: अम्बाह
सुनील सिंह तोमर	: अम्बाह
रवीकांत पाठक	: पिछोर
रंजीत बघेल	: सेंवढ़ा, दतिया
राहुल कुमार	: आगरा
छोटे सिंह भदौरिया	: मालनपुर
सूर्यप्रताप सिंह	: कोलारस
संतोष सिंह भदौरिया	: गोरमी
राजेश नरवरिया	: भिण्ड
हरिओम चतुर्वेदी	: करैरा
अरिमर्दन सिंह भदौरिया	: भिण्ड, क्राइम रिपोर्टर
निर्मला	: भिण्ड
राहुल खन्ना	:इंदौर
राजकुमार	: खेरागढ़, आगरा
शिवकांत ओझा	: रौन
आदित्य सिकरवार	: पोरसा
शिल्पा डोगरा	:ग्वालियर
वासुदेव मिश्रा	:ग्वालियर
शहनवाज खान	:श्योपुर

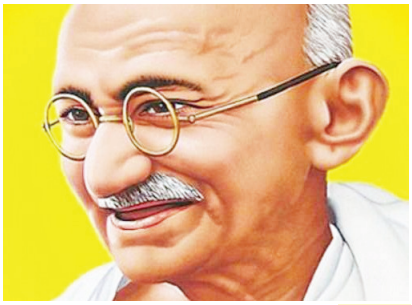

गांधी जी के विचारों.... 31

बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर 22

मां दुर्गा का... 33

ग्रामीण भारत 38

कृषि बिल पर घमासान

पिछले कई दिनों से कृषि क्षेत्र के लिए बनाये गये तीन कानूनों को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा हुआ किसानों ने देश के कई राज्यों में भारी विरोध प्रदर्शन और आगजनी की गई किसानों के साथ कांग्रेस भी केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना कृषि बिल के विरोध में बोल रही है वहीं दूसरी ओर राज्यसभा के 8 सांसदों को निलंबित किया गया। पंजाब से लेकर कर्नाटक तक किसान सड़कों पर हैं। इसकी तपिश दिल्ली तक भी पहुंच रही है। एक तरफ सरकार का दावा है कि इन कानूनों से बिचौलिए खत्म होंगे, भंडारण के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा। दूसरी तरफ विपक्ष, किसानों संगठनों के नेता और किसान इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त किए जाने की कोशिश मान रहे हैं।

किसान बिल को राष्ट्रपति द्वारा भी इन सुधारों को स्वीकृति प्रदान करने के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वहीं भाजपा के पुराने सहयोगी दल अकाली दल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसे संघीय ढांचे का उल्लंघन बता रहे हैं। कोरोना काल में अध्यादेश लाने में सरकार की नीयत पर सवाल उठे है। ऐसी स्थिति में किसान आन्दोलन आने वाले समय में चुनौती बन सकता है। तमाम बहस किसानों की आजादी और कृषि में पूंजीपतियों की दखल पर चल रही है। इसका तीसरा पक्ष आढ़ती व मजदूर अपनी जीविका के खतरे के रूप में देख रहा है। किसानों और उनके प्रतिनिधियों से बिना संवाद किये एवं राज्यों को विश्वास में लिये बगैर कोरोना जैसी महामारी के समय कृषि कानूनों को थोपना लोकतांत्रिक व्यवस्था का उल्लंघन है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल से हरसिमरन कौर के इस्तीफे के बाद यह विरोध उजागर हुआ है। किसान भारी संख्या में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था में कृषि राज्य का विषय है, ऐसा कहकर कुछ राज्य इसे नकार रहे हैं। देश में 86 प्रतिशत किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, ऐसे किसानों को एक देश-एक बाजार का लाभ नहीं मिल सकता। ऐसे किसानों को अपनी फसल को आसपास के बाजार में भी बेचना पड़ता है।

वैसे भी कृषि में खुले बाजार की व्यवस्था बिहार राज्य में 2006 से लागू है। दुनिया के सबसे साधन सम्पन्न देश अमेरिका में भी यह व्यवस्था 60 सालों से लागू है। जहां इसका किसानों को नुकसान और कम्पनियों को फायदा हुआ है। अमेरिका का एक किसान 2018 में ट्वीट कर लिखते हैं कि जो मक्का का भाव आज मिल रहा है, उससे ज्यादा कीमत उसके पिताजी को 1972 में मिली थी। यह मॉडल अमेरिका और यूरोप में किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो चुका है। विषय यह है कि 2006 में बिहार में एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया गया और सरकार द्वारा दलील दी गयी कि इससे निजी निवेश बढ़ेगा, निजी मंडियां खुलेंगी, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। आज बिहार का किसान 1300 रुपये कुन्तल गेहूं बेचने को मजबूर है। दूसरी तरफ पंजाब की मंडी में इसी गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये में पिछले वर्ष बेचा गया। हालांकि भारत सरकार के मंत्रियों और प्रधानमंत्री द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था को बनाये रखने का भरोसा दिया गया है, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाये बगैर पीछे हटने को तैयार नहीं

मोगा की ट्रेक्टर रैली में बोले राहुल-सत्ता में आएंगे तो खत्म करेंगे कृषि कानून

नए कृषि संबंधी कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में किसान और विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी कृषि कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में पंजाब साधते हुए कहा कि वो न्यूनत समर्थन मूल्य (एमएसपी), कृषि मंडी की व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। आगे राहुल ने कहा, इस कोरोना महामारी के समय में इन 3 कृषि कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? कानून लागू करने थे तो लोकसभा, राज्यसभा में बातचीत करते। पीएम कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, अगर किसानों के लिए कानून बनाए गए तो लोकसभा, राज्यसभा में खुलकर बात क्यों नहीं की। किसान क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए यूपी गए थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, कल मैं यूपी में था,उधर हिन्दुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम और सीएम ने उनको धमकाया है। ये है हिन्दुस्तान की हालत।

पहुंचे। ट्रैक्टर रैली में पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए राहुल ने वादा किया कि सत्ता में आते ही इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना

है। किसानों की मांग है कि देश में एक देश-एक भाव व्यवस्था लागू करनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, लेकिन मुख्यतः दो फसलों गेहूं और चावल की खरीद की जाती है। किसान इस व्यवस्था को फल, सब्जी सहित सभी फसलों में लागू किये जाने की मांग कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने के बावजूद भी दलहन, तिलहन और कपास के किसानों को खरीद न होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

अंतर्राष्ट्रीय संस्था ओसीईडी की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किसानों को वर्ष 2001 से 2016 के बीच फसल का समर्थन मूल्य न मिलने के कारण 45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री अगर देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं तो उन्हें चौथा कानून भी अनिवार्य रूप से बनाना होगा। फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून से घोषित समर्थन मूल्य से कम पर सभी कृषि विपणन को गैरकानूनी बनाते हुए खरीद की गारंटी दी जाए, जिससे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य स्थिर हो सके। चौथे कानून के बिना तीनों कानून निरर्थक साबित होंगे। कांट्रेक्ट फार्मिंग में कुल उत्पादन खरीदने व ग्रेडिंग पर रोक लगाये जाने, जीएम बीजों का प्रयोग न करने, किसानों को सिविल कोर्ट जाने की आजादी जैसे प्रावधान किये बिना यह कानून भी किसानों विरोधी साबित होगा। भारत सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त करने का दबाव है। भारत को पैसे की आवश्यकता है। बिना विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को मानें यह कर मिलना मुश्किल है। इसलिए आननफानन में तीनों कानून लाये गये हैं।

क्या है कृषि बिल 2020

कृषि बिल 2020 को लेकर समूचे पंजाब के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सरकार को विपक्ष के साथ-साथ अपने सहयोगियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कृषि बिल 2020 अध्यादेश के कारण अकाली दल और एनडीए का बर्षों पुराना गठबंधन टूट गया है, इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार में (केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रहीं हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया , और इसी क्रम में शिरोमणि अकाली दल ने भी एनडीए सरकार से खुद को अलग कर लिया। इसकी वजह बताते हुए दोनों नेताओं ने कहा कि वह ऐसे किसी मुद्दे का हिस्सा नहीं बन सकते जो किसानों के हितों के खिलाफ जाए, आज लाखों किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं और हम उनके साथ खड़े हैं।

रश्मि मिश्रा रश्मि
भोपाल

ऐसा क्या है कृषि बिल 2020 अध्यादेश में जिसका किसानों द्वारा इतना विरोध किया जा रहा है। प्रथम कृषि बिल (कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक2020) के तहत किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में, किसी भी व्यक्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। सरकार का कहना है कि इस बदलाव के जरिए किसानों को बेहतर दाम मिलेगा, अध्यादेश के जरिए सरकार देश में, ÷एक देश, एक बाजार की बाजार की नीति बनाना चाहती है। इस बिल का उद्देश्य कृषि विपणन समितियोंके बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और खरीदने की व्यवस्था बनाना है।

द्वितीय कृषि बिल अध्यादेश-(सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और आश्वासन और कृषि सेवा पर कृषि सेवा पर कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020- के तहत किसानों को फसल बुवाई के पहले ही तय मानक के मुताबिक, तय कीमत पर उत्पाद बेचने का अनुबंध करने की सुविधा दी गई है। इससे किसान को खरीददार ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वह किसी बड़े व्यापारी से बात करके तय कर सकता है कि जो फसल होगी उसकी कीमत क्या होगी, इस प्रकार किसानों को उत्पाद बेचने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। किसानों को बिचौलियों के शोषण से भी मुक्ति मिलेगी।

तीसरे कृषि बिल अध्यादेश(आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020) के तहत? आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, आलू ,प्याज जैसी वस्तुओं को हटाने की बात की जा रही है। इस विधेयक के जरिए यह व्यवस्था की गई है, युद्ध, अकाल , प्राकृतिक आपदा, असाधारण मूल्य वृद्धि जैसी परिस्थितियों में इन कृषि उपजों की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि बिल का जबरदस्त विरोध हो रहा है, आइए जानते हैं कि- क्यों हो रहा है इसका विरोध-बिल को लेकर किसानों और विपक्ष का सरकार पर आरोप है कि यह बिल किसानों के हित में नहीं है, इस बिल से किसानों के खेतों और मंडियों मैं बड़ी कारपोरेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा, किसानों को यह भी डर है कि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा, किसान संगठनों एवं विपक्षी दलों का यह भी आरोप है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बना दे जिससे किसान मंडी या उसके बाहर सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपना उत्पाद बेच पाएं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर किसान और सरकार के बीच तनातनी चल रही है।

किसानों के विकास के नए आयाम हेतु योजनाओं में पर्याप्त सुधार की जरूरत है

भारत में किसानों की दशा सुधारने के लिए बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है एक और कृषि और कृषि से जुड़े व्यवसाय में किसानों की अहम भूमिका होनी चाहिए लेकिन भारत देश में कृषि तो किसान ही करेंगे लेकिन कृषि से जुड़े व्यापार मैं किसानों की भूमिका नगण्य है किसानों से माल खरीद कर व्यापारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और किसान भूखों मरने की कगार पर पहुंच रहा है देश के हर प्रांत में किसान आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो रहा है और कई किसान तो थक हार कर मौत को ही गले लगा लेते हैं इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किसानों की हालत क्या है अब बात करें किसानों के विकास की या किसानों से जुड़ी योजनाओं की तो इन योजनाओं को ऐसे लोग बनाते हैं जिन्हें ठीक से कृषि का ज्ञान भी नहीं है वह लोग भला कृषि के विकास के लिए क्या योजनाएं बना पाएंगे उनको ठीक से यह भी मन नहीं मालूम गिर रवि की फसल में कौन-कौन सी फसलें बोई जाती हैं खरीफ की बुवाई मैं किन फसलों का योगदान होता है फिर वह कैसे किसान के विकास की प्रभावी योजनाएं बना पाएंगे यही हमारे देश का दुर्भाग्य है एसी में बैठ कर कृषि योजनाएं बनाने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि कृषि बहुत मेहनत का व्यवसाय है गर्मी और सर्दी से पृथक किसान किस तरह जूझता है यह उनको मालूम नहीं होता आज भी किसानों से जुड़ी योजनाओं को अमलीजामा वही लोग पहना रहे हैं जिनको कृषि का ठीक से ज्ञान भी नहीं है इसी कारण कृषि और कृषि से जुड़ी योजनाएं धरातल पर फेल हो रही हैं क्योंकि जो योजनाकार हैं उनको हकीकत का ज्ञान ही नहीं है और जो हकीकत के जानकार हैं उनको योजना बनाने का मौका ही नहीं मिलता इस कारण अधिकांश परियोजनाएं बनने के पहले की दम तोड़ देती हैं और कृषि विकास का मॉडल विकसित होने के पहले ही बिगड़ जाता है इसी का परिणाम है कि न तो किसान की आमदनी में वृद्धि होती है और नहीं किसान की स्थिति में सुधार हो पाता है योजनाएं वही ढाक के तीन पात बनकर रह जाती हैं किसान की स्थिति फटे हाल बनी रहती है इसमें सुधार करने के लिए ऐसे लोगों की कमेटी बनाई जाए जो किसान की समस्या को हकीकत में वर्णित कर सके और उसके आमदनी वाले स्रोतों का इन योजनाओं में समावेश होना चाहिए तभी हम किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार की व्यापक योजना बना पाएंगे इसी से हकीकत में किसान की आमदनी बढ़ पाएगी

शैलेश सिंह कुशवाह
वरिष्ठ पत्रकार ग्वालियर

कृषि बिल पर 'मोदी वाणी'

किसानों की मजबूती से रखी जाएगी आत्मनिर्भर भारत की नींवः पीएम मोदी

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2014 के बाद से ही किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है एवं कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु कई योजनाओं को लागू किया गया है। इसी कड़ी में, अभी हाल ही में भारतीय संसद ने कृषि क्षेत्र से सबंधित तीन क़ानूनों को अपनी मंजूरी दी है। यह कृषि क्षेत्र के लिए एक विशाल परिवर्तक के तौर पर सिद्ध होने जा रहा है एवं इसके कारण कृषि क्षेत्र में निजी निवेशक अपने निवेश को बहुत भारी मात्रा में बढ़ा सकेंगे।

मोदी सरकार के आने के बाद से किसानों की भलाई के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों में एक अगली कड़ी ही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो-जो ज़रूरी है वह सब केंद्र सरकार करने का प्रयास कर रही है। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए खेती के साथ-साथ पशुपालन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः केंद्र सरकार ने देश में डेयरी उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। नीली अर्थव्यवस्था (मछली पालन) एवं बागवानी पर भी विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। नीति आयोग ने बताया है कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों को अपनी 70 प्रतिशत आय खेती के माध्यम से अर्जित करनी होगी एवं 30 प्रतिशत आय पशुधन के माध्यम से अर्जित करने पर फ़ोकस करना होगा। साथ ही, किसानों को उच्च मूल्य की फ़सलों की ओर भी जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांव, किसान और देश का कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं तथा ये जितने मजबूत होंगे, आत्मनिर्भर भारत की नींव भी उतनी ही मजबूत होगी. आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 69वीं कड़ी में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कठिन दौर में कृषि क्षेत्र और देश के किसानों ने फिर अपना दमखम दिखाया. उन्होंने कहा, हमारे यहां कहा जाता है कि जो जमीन से जितना जुड़ा होता है, वह बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अधिक रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है. संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है. प्रधानमंत्री ने कहा, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं. ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी. पीएम मोदी ने हमारे किसान और गांव आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। किसान जितने मजबूत होंगे आत्मनिर्भर भारत की नींव उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि तीन-चार साल पहले महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को के दायरे से बाहर कर दिया गया था। इस बदलाव ने कैसे महाराष्ट्र में फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली, इसका उदाहरण हैं श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये किसानों का समूह है। ग्रामीण युवा, सीधे बाजार में, खेती और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को मिलता है। पुणे और मुंबई में किसान साप्ताहिक बाजार चला रहे हैं। इन बाजारों में, लगभग 70 गांवों के साढ़े चार हजार किसानों का उत्पाद सीधे बेचा जाता है, इस प्रक्रिया में कोई बिचौलिया नहीं होता है। पीएम मोदी ने कहा, हर परिवार में कोई-न-कोई बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई उर्जा भरते देते हैं।

हिमाचल प्रदेशः पीएम मोदी ने किया 9.02 किलोमीटर लंबी

अटल रोहतांग टनल का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रोहतांग में कहा कि अटल जी की सरकार जाने के बाद, जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद, जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। अटल रोहतांग टनल के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में ही आधुनिक अस्त्र-शस्त्र बने, मेक इन इंडिया हथियार बनें, इसके लिए बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। लंबे इंतजार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब हमारे सिस्टम का हिस्सा है। देश की सेनाओं की आवश्यकता अनुसार प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन दोनों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी के साथ ही एक और पुल का नाम जुड़ा है- कोसी महासेतु का। बिहार में कोसी महासेतु का शिलान्यास भी अटल जी ने ही किया था। 2014 में सरकार में आने के बाद कोसी महासेतु का काम भी हमने तेज करवाया। कुछ दिन पहले ही कोसी महासेतु का भी लोकार्पण किया जा चुका है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अटल टनल की तरह ही अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप 40-45 साल तक बंद रही। क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद, अभूतपूर्व तेजी लाई गई। नतीजा ये हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़कर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। उन्हनो कहा कि एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से 2014 में अटल टनल का काम हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर पूरा हो पाती। आपकी आज जो उम्र है, उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिन आता। उनका सपना पूरा होता।

लगातार 20 साल से चुनी हुई सरकारों का नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी

एक और मील का पत्थर पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर 20वें साल में प्रवेश कर गए हैं। नरेंद्र मोदी बिना कोई ब्रेक लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित राज्य से लेकर केंद्र के मुखिया के रूप में उनके

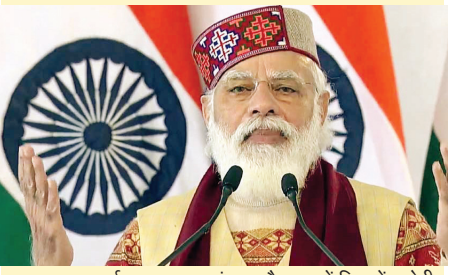

कार्यकाल का 20वां साल है। बता दें कि नरेंद्र मोदी गुजरात में लगातार तीन बार मुख्यमंत्री के बाद लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पहला कार्यकाल 7 अक्टूबर 2001 को शुरू किया था। इस तरह से वह 2002, 2007 और 2012 में तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान ही मोदी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी, राज्य से लेकर पूरे देश में उनकी लोकप्रियता का ही कमाल था कि साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया। गुजरात में उनके काम को देखते हुए नरेंद्र मोदी को 2013 में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया।

राजमाता विजया राजे सिंधिया के सम्मान में पीएम मोदी ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 100वीं जयंती पर 100 रुपये के सिक्के का अनावरण किया। कोरोना वायरस की वजह से एक वर्चुअल समारोह के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिक्के को देश को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकता यात्रा के समय राजमाता ने मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पर कराया था, इतने सालों बाद आज उनका वही नरेंद्र देश का प्रधानसेवक बनकर उनकी अनेक स्मृतियों के साथ आपके सामने है। उन्होंने कहा कि राजमाता ने अपना जीवन गरीब लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। उनके लिए राजसता नहीं बल्कि जन सेवा अहम थी। नारी शक्ति के बारे में वो विशेष तौर पर कहती थीं कि जो हाथ पालने को झुला सकते हैं, तो वो विश्व पर राज भी कर सकते

श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी

हैं। आज भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं हैं, देश को आगे बढ़ा रही हैं। तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाकर, देश ने राजमाता सिंधिया के महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया है। ये भी कितना अद्भुत संयोग है कि रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया था, उनकी जन्मशताब्दी के साल में ही उनका ये सपना भी पूरा हुआ है। राजमाता के आशीर्वाद से देश आज विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गांव, गरीब, दलित-पीड़ित-शोषित-वंचित, महिलाएं आज देश की पहली प्राथमिकता में हैं। राजमाता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व थीं। साधना, उपासना, भक्ति उनके अन्तर्मन में रची बसी थी। लेकिन जब वो भगवान की उपासना करती थीं, तो उनके पूजा मंदिर में एक चित्र भारत माता का भी होता था। भारत माता की भी उपासना उनके लिए वैसी ही आस्था का विषय था।आपातकाल के दौरान तिहाड़ जेल से राजमाता ने अपनी बेटियों को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने चिट्ठी में जो लिखा था उसमें बहुत बड़ी सीख थी। उन्होंने लिखा था- अपनी भावी पीढ़ियों को सीना तान कर जीने की प्रेरणा मिले इस उद्देश्य से हमें आज की विपदा को धैर्य के साथ झेलना चहिए।कोई भी साधारण व्यक्ति जिसके अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, देश सेवा की भावना है, वो इस लोकतंत्र में भी सत्ता को सेवा का माध्यम बना सकता है। राजमाता ने जीवन का महत्वपूर्ण कालखंड जेल में बिताया, आपातकाल के दौरान उन्होंने जो-जो सहा उसके साक्षी हममे से बहुत से लोग हैं।विवाह से पहले राजमाता जी किसी राज परिवार से नहीं थीं, एक सामान्य परिवार से थीं, लेकिन विवाह के बाद उन्होंने सबको अपना भी बनाया और ये पाठ भी पढ़ाया कि जनसेवा के लिए, राजकीय दायित्व के लिए किसी खास परिवार में जन्म लेना ही जरूरी नहीं।

बारह राज्यों की 56 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उप-चुनाव

सत्ता का सिंहासन तय करेंगे उपचुनाव

आम तौर पर किसी उप-चुनाव को लेकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर बहुत दिलचस्पी नहीं होती, क्योंकि उसका राजनीतिक प्रभाव भी सीमित होता है। लेकिन जिन बारह राज्यों की 56 विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा निर्वाचन आयोग ने की है, उनकी प्रतीक्षा काफी समय से की जा रही थी। खासकर मध्य प्रदेश के लिहाज से ये उप-चुनाव काफी अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनके परिणाम प्रदेश की राजनीति पर निर्णायक असर डालने की स्थिति में हैं। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा की इस वक्त 28 सीटें खाली हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस विधायकों द्वारा पाला बदलकर भाजपा के साथ खड़े होने से खाली हुई हैं। इस दलबदल के कारण वहां लंबे अंतराल के बाद बनी कांग्रेस की सरकार धराशायी हो गई थी, मगर सत्ताधारी भाजपा के पास आज भी स्पष्ट बहुमत से नौ सीटें कम हैं, यही कारण है कि इन उप-चुनावों पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए मध्य प्रदेश के ये उप-चुनाव 'करो या मरो' का मुकाम हैं, इसीलिए तिथि की घोषणा के बहुत पहले से दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता मतदाताओं से संवाद बनाने में जुट गए थे। हालांकि, इसका एक अफसोसनाक पहलू यह भी देखने को मिला कि कई कार्यकर्ता सम्मेलनों में दोनों पार्टियों के नेताओं ने महामारी के मद्देनजर मान्य एहतियातों का भी ख्याल नहीं रखा। वह भी तब, जब मध्य प्रदेश के कई शीर्ष नेता खुद इस वायरस की जद में आ चुके हैं। दरअसल, सरोकारी सियासत की जगह सत्ता की राजनीति हावी हो जाए, तो वह मानवीय पक्षों की परवाह की मोहलत नहीं देती। बहरहाल, अब जब राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है, तो स्थानीय प्रशासन को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप यह सुनिश्चित करना होगा कि ये उप-चुनाव प्रदेश में महामारी बढ़ाने वाले साबित न होने पाएं और संबंधित क्षेत्रों की जनता को उनका लोकप्रिय प्रतिनिधि भी मिल सके। संविधान निर्माताओं ने एक तय अवधि के भीतर खाली सीटों पर उप-चुनाव कराने का प्रावधान ही इसीलिए किया है, ताकि शासन में प्रत्येक क्षेत्र की नुमाइंदगी होती रहे। अगर महामारी न फैली होती, तो इन तमाम क्षेत्रों को उनका निर्वाचित प्रतिनिधि पहले ही मिल चुका होता। इस पृष्ठभूमि में निर्वाचन आयोग ने यह उचित फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही इन उप-चुनावों को भी संपन्न करा लिया जाए। ये चुनाव मणिपुर-नगालैंड से लेकर कर्नाटक-तेलंगाना व गुजरात से उत्तर प्रदेश तक देश के सभी कोणों में और बिल्कुल अलग परिस्थिति में हो रहे हैं। इनकी सफलता और मुश्किलों से चुनाव आयोग को असाधारण स्थितियों में तैयारी के सबक भी सीखने को मिलेंगे। अब मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को यह तय करना है कि वे कर्नाटक की तरह मौजूदा सरकार को स्थिरता देने के लिए वोट करते हैं या फिर दलबदल के खिलाफ अपना जनादेश देते हैं। पर इन उप-चुनावों की एक खास बात यह भी है कि इनमें से ज्यादातर सीटें भाजपा शासित राज्यों में हैं। मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात की आठ, उत्तर प्रदेश की सात सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। अन्य राज्यों में सरकारों की सेहत पर इनके परिणामों का कोई असर भले न पड़े, मगर ये उनकी लोकप्रियता का अंदाजा तो देंगे ही।

कौन जीतेगा बिहार का दिल

बिहार में जैसे-जैसे चुनावी राजनीति मुखर हो रही है, राजनीतिक तस्वीर के नये बिंब उभरे हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की मुखरता दिग्गज राजनीतिक दलों पर भारी पड़ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के फैसले ने राजनीतिक पंडितों को चौंकाया है। हालांकि, पहले भी एलजेपी प्रवासी श्रमिकों, कोरोना संक्रमण प्रबंधन, बाढ़ आदि के मुद्दे पर सत्तारूढ़ जद-यू पर हमलावर रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जद-यू अर्से से बिहार की सत्ता पर काबिज रही है। पिछला चुनाव जद-यू ने राजद व कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा और सरकार बनायी। फिर पाला बदलकर भाजपा के साथ सरकार बनायी। दरअसल, बिहार में अब नयी पीढ़ी के राजनेताओं ने दस्तक दी है।

बिहार में लालू-नीतीश दौर के बाद नयी पीढ़ी बिहार को नेतृत्व देने को तैयार हो रही है। कहा भी जा रहा है कि एलजेपी के चिराग पासवान 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एक वजह यह भी है कि जद-यू में नीतीश के बाद दूसरी पंक्ति का नेतृत्व विकसित नहीं हो पाया है। बिहार की राजनीति में ये युवा उस शून्य को भरने की कोशिश कर रहे हैं। पेशे से नीतीश कुमार की तरह इंजीनियर चिराग पासवान बिहार की राजनीति की नयी इंजीनियरिंग की तलाश में नजर आ रहे हैं। उनका मकसद एलजेपी का जनाधार बढ़ाकर भविष्य की राजनीति का आधार तैयार करना भी है। चिराग पासवान यह महसूस कर रहे हैं कि राज्य में सत्ता के खिलाफ जो जनाक्रोश है, उसे वे जद-यू के खिलाफ चुनाव लड़कर पार्टी के जनाधार के रूप में हासिल कर सकते हैं। हालांकि, इस दांव को कई अन्य घटक भी प्रभावित करेंगे। उसमें यह भी निर्भर करेगा कि राजद व कांग्रेस कितने मजबूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारते हैं। बदले हालात में उनकी चुनावी रणनीति कैसे सिरे चढ़ती है। यह भी कि राजनीति के चतुर सुजान नीतीश कुमार चुनाव आते-आते कौन-सा नया पैंतरा चलते हैं। हालांकि, बिहार की राजनीति में एलजेपी ऐसी ताकत कभी नहीं रही कि अपने बूते सरकार बना सके। वह अक्सर किंग मेकर की भूमिका में रही। वह बदलती हवा के साथ पाला बदलकर सरकार बनाती रही है। अब राजग से अलग होकर लड़ने से उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी उजागर हुई है। पहली नजर में मामला टेढ़ा नजर आता है कि बिहार में लोजपा राजग से अलग होकर चुनाव लड़े और केंद्र में राजग में बनी रही। चुनावी पोस्टरों में लिखे नारे- 'मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं' बहुत कुछ कहते हैं। कहा जा रहा है कि लोजपा बंदूक तो चला रही है, मगर कंधा किसका है? क्या यह सब पर्दे के पीछे से बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। सवाल यह भी है कि जब चिराग पासवान तमाम मुद्दों पर नीतीश सरकार पर हमलावर थे तो भाजपा ने उन्हें समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? दरअसल, भाजपा भी मानकर चल रही है कि राज्य में सत्ता विरोधी रुझान नीतीश के खिलाफ है, मगर राज्य में मोदी की लोकप्रियता बनी हुई है। हाल में प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिये जो सोलह हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की ताबड़तोड़ घोषणाएं की हैं, उसका लाभ भी भाजपा को मिलेगा। लोजपा भी सोच रही है कि यदि भविष्य में भाजपा-जद-यू गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो अकेले लड़कर हासिल सीटों के बूते वह किंग मेकर की भूमिका में आकर नीतीश की पार्टी पर दबाव बना सकती है। बहरहाल, अभी चुनाव से पहले बिहार की राजनीति कई तरह से करवट लेती नजर आयेगी। पिछला चुनाव जद-यू व भाजपा ने अलग होकर लड़ा था, अत- सीटों को लेकर भी गठबंधन में टकराहट सामने आयेगी। जद-यू में कई वरिष्ठ नेता नीतीश पर दबाव बना रहे हैं कि लोजपा की पहल के बाद पार्टी को राजग से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। संभव है नीतीश इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर दबाव बनायें। भाजपा भी सोचेगी कि पुराने सहयोगी शिवसेना व अकाली दल के बाद क्या वह जद-यू को भी खोने को तैयार है।

उपचुनाव:28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग, बिहार के साथ 10 नवंबर को ही नतीजे आएंगे; 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे

3 नवंबर को उपचुनाव, 10 को आएंगे नतीजे

शिवराज, कमलनाथ, सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर

मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव होना है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 16 अक्टूबर को नामांकन करने की अंतिम तारीख होगी। मध्यप्रदेश के उपचुनावों में भाजपा अपनी सत्ता बचाने और कांग्रेस नेता कमलनाथ छह महीने पहले खोई सत्ता वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की है। मध्यप्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। पहली बार प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसकी वजह प्रदेश में मार्च में हुआ सियासी फेरबदल है। इसी साल 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद अल्पमत में आई कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने से 22 सीटें खाली हो गई थीं। इसके बाद जुलाई में बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी और नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कसडेकर ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा जॉइन कर ली। फिर मांधाता विधायक ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा का झंडा पकड़ लिया। इसके अलावा, तीन विधायकों का निधन हो गया। यानी कुल 28 विधानसभा सीटें खाली हो गईं। सिंधिया के साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए थे। इनमें 16 सीटें उनके प्रभाव क्षेत्र ग्वालियर-चंबल की हैं। यह सिंधिया के प्रभाव वाला इलाका है। इन सीटों पर भाजपा को जिताना उनके लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने अब तक 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भाजपा के नामों की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन इतनी संख्या में विधायकों को जिता ले कि एक बार फिर सियासी उठापटक की सूरत बन जाए। राज्य की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें

25 सीटों पर उसके प्रत्याशी लगभग तय माने जा रहे हैं। इनमें 22 वह विधायक होंगे जो सिंधिया के साथ भाजपा में आए और तीन वे जिन्हें सीएम शिवराज ने शामिल कराया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा विधायक जिताकर अपनी सत्ता और मजबूत करना चाहेंगे। वहीं, कमलनाथ इस बात के लिए जोर लगाएंगे कि उपचुनाव में कांग्रेस से 27 पर पहले कांग्रेस का कब्जा था। प्रदेश में 230 सदस्यीय राज्य विस में बहुमत के लिए 116 सीटें होना जरूरी हैं। अगर भाजपा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसकी सरकार और स्थिर होगी। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश है कि वह 20 या उससे ज्यादा सीटें जीत ले, जिससे की एक बार फिर प्रदेश में सत्ता पलट सकती है।

शिवराज की बचेगी कुर्सी या फिर कमलनाथ का चलेगा जादू

कौन मारेगा बाजी

कमलनाथ सरकार के केवल 15 महीने में गिरने के बाद सत्ता में आए शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहेगी या फिर चली जाएगी, इसका फैसला 10 नवंबर को हो जाएगा। राज्य की 28 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। ये उपचुनाव कमलनाथ के के लिए भी काफी अहम साबित होंगे। आंकड़ों के आधार पर तो शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी के लिए कोई खतरा नहीं दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा के पास 107 विधायक हैं। ऐसे में उसे बहुमत के लिए 27 में से सिर्फ नौ सीटें जीतने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए सभी 27 सीटें जीतने की जरूरत पड़ेगी। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन विधायकों के टूटने के बाद अब उसके 89 विधायक ही रह गए हैं। अगर दोनों दल उपचुनाव के परिणामों के बाद बहुमत का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाते हैं, तो सत्ता की चाबी एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के दो, समाजवादी पार्टी के एक और चार निर्दलीय विधायकों के पास चली जाएगी। फिलहाल कमलनाथ और शिवराज, दोनों यही दावा कर रहे हैं कि उपचुनावों के बाद उनकी पार्टी को बहुमत मिल जाएगा। उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में कांग्रेस ने भाजपा से कहीं ज्यादा तेजी दिखाई है। कांग्रेस ने 29 सितंबर तक 15 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, जबकि भाजपा एक भी नाम तय नहीं कर पाई। वैसे, मुख्यमंत्री के एक करीबी सूत्र ने आउटलुक को बताया, वे उपचुनावों के लिए अप्रैल-जुलाई में ही एक-एक सीट का बारीकी से अध्ययन कर चुके हैं। कमलनाथ का सिंधिया परिवार के प्रभाव वाले ग्वालियर-चंबल क्षेत्र पर ज्यादा जोर है। इस क्षेत्र में उपचुनाव की 27 सीटों में से 16 सीटें आती हैं। इन क्षेत्रों में कमलनाथ ज्यादातर उन लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद असहज महसूस कर रहे हैं। कमलनाथ की यह रणनीति कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान से भी दिखती है। अब तक घोषित 15 सीटों में से तीन पर ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है, जो पहले भाजपा में थे। अगली लिस्ट में भी कई ऐसे नेताओं को टिकट दिए जा सकते हैं जो सिंधिया के करीबी रहे हैं, लेकिन भाजपा का दामन नहीं थामना चाहते। दूसरी तरफ, भाजपा उन नाराज नेताओं को मनाने में लगी हुई है, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथियों के भाजपा में शामिल होने के बाद अपना राजनीतिक करियर खत्म होता दिख रहा है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय से जुड़े जयभान सिंह पवैया ने तो सिंधिया के करीबियों के लिए चुनाव प्रचार करने से भी मना कर दिया है हालांकि मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी.शर्मा इन बातों को नकारते हुए कहते हैं, पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी 27 सीटों पर जीत हासिल करेगी। एक वरिष्ठ मंत्री का कहना है, सिंधिया ने अपने 14 विधायकों को मंत्री बनवाकर उन्हें टिकट दिलाना पक्का कर लिया है। वे चार से छह टिकट और चाहते हैं। हमारे लिए उन नेताओं की उम्मीदवारी को नजरअंदाज करना काफी मुश्किल हो रहा है, जो पिछले चुनाव में जीत कर आए थे। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ ने लोगों के बीच कांग्रेस की स्थिति जानने के लिए तीन एजेंसियों को जिम्मेदारी दी थी, जिसके शुरुआती परिणाम पार्टी के लिए उत्साहजनक हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से यह भी कहा गया है कि वे मतदाताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया के धोखे और चौहान सरकार की किसान विरोधी नीतियों के बारे में भी जोर-शोर से बताएं। इसके अलावा वह सचिन पायलट को भी प्रचार के लिए बुला रही है। पायलट के जरिए कांग्रेस की कोशिश युवाओं को लुभाने की है। दूसरी तरफ, शिवराज सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के मकसद से प्रदेश वासियों के लिए नौकरियों में आरक्षण की बात की है, ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में कई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की भी घोषणा की है।

हाथरस कांड जिम्मेदार कौन? मानवता शर्मसार

आखिर कब रूकेगी दरिंदगी?

“

हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ हुई हैवानियत में न केवल समाज की जीभ काटने की चेष्टा हुई है, बल्कि रीढ़ को भी तोड़कर साफ संकेत दे दिया गया है। समाज को सबक लेना चाहिए, अब न केवल नई जीभ, बल्कि नई रीढ़ के साथ समाज को सामने आकर मुकाबला करना होगा। यह घिनौनी हैवानियत दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। हाथरस के बाद बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर, बारां इत्यादि में भी मानवता शर्मसार हुई है।

महिलाओं की सुरक्षा का विषय एक बार फिर हमें झकझोर कर न सिर्फ सोचने पर मजबूर, बल्कि शर्मसार भी कर रहा है। जिस अपराध से हमारी मानव सभ्यता को सबसे पहले दामन छुड़ा लेना चाहिए था, उसी अपराध को हमारे बीच कई लोग ऐसे अंजाम देते हैं कि इंसानियत पर भी शक होने लगता है। हाथरस में 19 वर्षीय दलित लड़की के साथ हुई हैवानियत में न केवल समाज की जीभ काटने की चेष्टा हुई है, बल्कि रीढ़ को भी तोड़कर साफ संकेत दे दिया गया है। समाज को सबक लेना चाहिए, अब न केवल नई जीभ, बल्कि नई रीढ़ के साथ समाज को सामने आकर मुकाबला करना होगा। यह घिनौनी हैवानियत दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। हाथरस के बाद बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर, बारां इत्यादि में भी मानवता शर्मसार हुई है।

हाथरस का इस तरह देश-दुनिया में चर्चा में आना न केवल दुखद, बल्कि शर्मनाक भी है। जो ज्यादती 14 सितंबर को हुई थी, उससे जुड़े जितने सच लोगों को नहीं पता, उससे कहीं ज्यादा अफवाह और सवाल हवा में हैं। बताने की कोशिश में इतने संशय पैदा हो गए हैं या छिपाने की कोशिश में? यह विडंबना ही है या समझ से जुड़ी कोई त्रासदी कि आज के सक्षम दौर में भी सूचनाओं पर खुले पहरे बिठाने की कवायद दिल्ली की सड़कों से हाथरस में बूलगढ़ी की गलियों

तक नुमाया हुई है। क्या इस मामले को बूलगढ़ी या हाथरस के स्तर पर ही न्याय की दहलीज तक नहीं पहुंचाया जा सकता था? यदि अनेक कानूनी प्रावधानों के बावजूद हम महिलाओं और उसमें भी दलित महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें क्या किसी आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए? बलात्कार की शिकार युवती की हालत यदि ज्यादा खराब थी, तो उसे पहले ही इलाज के लिए दिल्ली क्यों नहीं लाया गया? कौन लोग थे, जो हाथरस में उस युवती को न्याय दिलाने का कर्तव्य निभा रहे थे? इस मामले में कदम-कदम पर न केवल व्यावहारिक, बल्कि इतनी विधिगत गलतियां हुई हैं कि यह मामला प्रशासन के लिए एक मिसाल बन गया है। देश के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो चुके इस प्रकरण के जरिए प्रशासन के विद्यार्थियों को पढ़ाया-सिखाया जा सकता है कि किस चरण में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। पिछले वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि देश

हर रोज 87 दुष्कर्म, कुल 32033 मामले दर्ज, एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा

हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात से पूरा देश हिला हुआ है. इस जघन्य कांड के बाद देशभर में आक्रोश है और इंसाफ की मांग कर रहे हैं. इस बीच एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि साल 2019 में हर रोज करीब 87 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं. देश में दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, 2018 के मुकाबले 2019 में दुष्कर्म के मामलों में सात फीसद की वृद्धि हुई. हालांकि, इस अवधि में हत्या और अपहरण की घटनाओं में मामूली गिरावट दर्ज की गई. एनसीबी के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में देश में प्रतिदिन औसतन 87 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए. जबकि, महिला उत्पीड़न से जुड़े कुल लगभग 4,05,861 मामले दर्ज हुए. साल 2018 में देशभर में महिला उत्पीड़न के कुल लगभग 3,78,236 मामले दर्ज हुए थे. आंकड़ों के अनुसार, 2019 में दुष्कर्म के कुल 32,033 मामले दर्ज किए गए, जो महिला उत्पीड़न को लेकर दर्ज कुल मामलों में से 7.3 प्रतिशत है.

2017 से लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामले

साल 2018 में पूरे देश में दुष्कर्म के कुल 33,356 मामले दर्ज हुए जो 2017 से ज्यादा है. 2017 में कुल 32,5,59 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए. वहीं दूसरी तरफ हत्या और अपहरण के मामलों में कमी आई है. आंकड़ों के अनुसार, 2018 में हत्या के 29,017 मामले दर्ज किए गए. जबकि 2019 में यह आंकड़ा 28,918 लोगों की हत्या हुई. इसी तरह 2019 में अपहरण के 1,05,734 मामले में दर्ज हुए.

भर में हर दिन बलात्कार के 88 मामले सामने आते थे। इस साल भी स्थिति बहुत अलहदा नहीं होगी। लेकिन बेशक यह कुशल प्रशासन का ही नतीजा है कि चंद मामले ही चर्चा में आते हैं, ज्यादातर मामलों में स्थानीय स्तर पर ही यथोचित कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसे में, यह समझना कठिन नहीं कि हाथरस का मामला विरल मामलों में कैसे शामिल हो गया? आखिर क्या जरूरत थी कि पीड़ित परिवार तक पहुंचने की तमाम कोशिशों पर पहरे बिठा दिए गए? कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर कितने पत्रकारों की फोन टैपिंग हुई है? जब प्रशासन जरूरत से ज्यादा सवाल पैदा करने लगता है और जरूरत से कम जवाब देने लगता है, तो हालात ऐसे ही बिगड़ने लगते हैं। नेताओं को बलपूर्वक हाथरस जाने से रोका गया, लेकिन जब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने दिया गया, तो क्या कोई भूचाल आ गया? हर राजनीतिक पार्टी और मीडिया को अपना दायरा पता है, सब सच जानना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सच और जवाब ही सबसे अच्छा समाधान है। हो सकता है, प्रशासन सही हो, पर आज सच जानने वालों पर पहरे बिठाने की कोशिश उसका सबसे बड़ा दोष है। न्याय कोई एकपक्षीय मामला नहीं होता, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। प्रशासन ही नहीं, पूरे समाज के लिए यह सोचने का समय है। बलात्कार जैसे अक्षम्य अपराध के विरुद्ध सामाजिक बाड़ेबंदियां पलक झपकते टूट जानी चाहिए। धार्मिक, सामाजिक, इंसानी या सांविधानिक, ऐसा कोई आधार नहीं है, जो हमें जाति के आधार पर पक्षपात के लिए प्रेरित करता हो। खेमेबाजी राजनीति के लिए मुफीद भले हो, लेकिन वह हमें सार्वभौमिक सुरक्षा का एहसास कतई नहीं करा सकती और सुरक्षा करना तो दूर की कौड़ी है। हाथरस से हमें सबक लेने की जरूरत है, ताकि फिर ऐसे छिपने-छिपाने की जरूरत न पड़े।

वहीं दूसरी ओर व्यवस्था की टालमटोल, लापरवाही, उदासीनता का ही नतीजा है कि निर्भया के समय के बाद भी भारतीय समाज में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। निर्भया के समय देश में भावनाओं में उबाल आया था और ऐसा लगा कि हम सुधार की दिशा में बढ़ेंगे। अब आंकड़े बताते हैं कि पिछले दस वर्ष में महिलाओं के शोषण की आशंका में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 32,033 बलात्कार हुए थे, जिसमें से करीब 11 प्रतिशत मामले दलित महिलाओं से जुड़े थे। महिलाओं के सम्मान या पूजा के बारे में किसी भी धर्म की कथनी पर जाने की बजाय हमें केवल करनी की चिंता करनी चाहिए। बड़ी-बड़ी बातों का समय बीत चुका है, अब बड़ी कार्रवाई का समय है। आज यौन अपराधों और यौन हिंसा को पूरी गंभीरता से संज्ञान में लेने की जरूरत है। काश! हमारे राजनीतिक दल इस मुद्दे पर पूरी ईमानदारी से ध्यान देते, तो देश में बलात्कार के मामले कम से कम हो रहे होते। निर्भया के समय जो कानून बने थे, कानून में जो सुधार हुए थे, उन्हें लोग भूल चुके हैं, तो क्या हमारी व्यवस्थाएं भी भूल चुकी हैं? यह एक ऐसा अपराध है, जो अपने उपचार में पूरी संवेदना की मांग करता है। जहां पूरी व्यवस्था को अपनी पूरी ममता और मरहम के साथ पीड़ित के पक्ष में खड़ा हो जाना चाहिए, वहीं उत्पीड़क के प्रति दया की गुंजाइश न के बराबर होनी चाहिए। सामाजिक, धार्मिक, सांविधानिक आधार पर कोई तर्क ऐसा नहीं, जिससे किसी बलात्कारी को किसी आड़ में पल भर के लिए भी बचाया जा सके। समाज में गुस्सा आज फिर चरम पर है, यह इशारा है कि कानून-व्यवस्था से लोग संतुष्ट नहीं हैं। आज फिर गांधीजी के सत्य, प्रेम, अहिंसा और शास्त्रीजी की दृढ़ता को याद कर आगे बढ़ने की जरूरत है। तंत्र को पूरी कड़ाई से अपने व्यवहार को परखना होगा और राजनेताओं को अपने दायरे में समदर्शी भाव रखना होगा। कानून-व्यवस्था के मामले में कम से कम राजनीति हो और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने राज्य में ऐसे अपराधों को काबू में करने के हरसंभव प्रयास करें, तो इससे बढ़कर आज कोई दूसरी राष्ट्र सेवा नहीं होगी।

हाथरसः राहुल गांधी बोले- यूपी सरकार नहीं कर पाएगी मनमानी, प्रियंका गांधी ने भी उठाए सवाल

हाथरस की घटना ने राहुल को खुद को एक नेता के रूप में भुनाने का एक और मौका दिया है जो सही मुद्दों को उठाता है और उन्हें अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाता है - या कम से कम लड़ाई जारी रखता है। बेशक, स्पष्ट राजनीतिक और चुनावी विचार हैं, जिन्होंने उसके हस्तक्षेप को आकार दिया होगा। उनकी पार्टी यूपी में प्रियंका के आरोप के तहत पुनर्जीवित होने की मांग कर रही है और दलित एक बड़े वोट बैंक हैं। बिहार, जहाँ इस महीने के अंत में चुनाव होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से दलित वोटबैंक है और हाथरस के आतंक का बदला पूर्वी राज्य में भी महसूस किया जा रहा है। कांग्रेस बिहार में भी एक खिलाड़ी है लेकिन हाथरस में दलितों के साथ राहुल की सार्वजनिक एकजुटता उनकी पार्टी को कुछ हद तक इस घटना को भुनाने की अनुमति दे सकती है, खासकर तब जब वह और सड़कों पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने जबकि दलितों की पार्टी कहे जाने वाली मायावती की बसपा, रामविलास पासवान की लोजपा जैसी पार्टियाँ और अन्य लोग होंठ हिलाते रहे। यमुना एक्सप्रेसवे पर यूपी पुलिस के जवानों से घिरे राहुल गांधी , यकीनन यह उनकी सबसे प्रबल राजनीतिक छवि थी। अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और समर्थकों की एक बड़ी भीड़ के साथ, राहुल कथित 19 वर्षीय दलित लड़की के परिवार से मिलने के लिए हाथरस पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिनकी कथित बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई।

गाँधी भाई-बहनों पर भयंकर हाथरस की घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप भाजपा की ओर से आया है। आदित्यनाथ सरकार की ताकत, निस्संदेह, पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा राहुल और प्रियंका को हाथरस पहुंचने से रोकने के लिए कार्रवाई के रूप में प्रदर्शित हुई है - यह जोड़ी ग्रेटर नोएडा को भी पार नहीं कर सकी। मगर बीजेपी के आलोचकों और ट्विटर पर कई लोगों द्वारा इसकी प्रशंसा हुई। कईयों ने राहुल को एकमात्र विपक्षी नेता के रूप में माना जो लगातार सही मुद्दों को उठाने का साहस दिखाते हैं।

हाथरस में 19 वर्षीय दलित युवती की हत्या और कथित बलात्कार के मामले में कांग्रेस पार्टी मुखर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। लगभग एक घंटे की हुई इस मुलाकात में कांग्रेस के दोनों नेताओं ने परिवार का हाल जाना और सांत्वना दी। इसके बाद राहुल और प्रियंका ने ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर प्रहार किए। राहुल गांधी ने कहा कि यूपी सरकार चाह कर भी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब इस देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा मैं हाथरस के पीड़ित परिवार से मिला और उनका दर्द समझा। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम इस मुश्किल वक़्त में उनके साथ खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाने में पूरी मदद करेंगे। यूपी सरकार चाह कर भी मनमानी नहीं कर पाएगी क्यूँकि अब इस देश की बेटी को इन्साफ़ दिलाने पूरा देश खड़ा है।

समाज को विभाजित करने वालों की साजिश सफल नहीं होने देंगेः सीएम योगी

लखनऊ. हाथरस मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग समाज को जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर विभाजित करते रहे हैं, वे अब भी कर रहे हैं. वे विकास नहीं देख सकते हैं और इसलिए वे नए षड्यंत्र रच रहे हैं. एक व्यक्ति की मौत पर राजनीति करने वालों को पहचानना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम किसी की भी साजिश को सफल नहीं होने देंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसियों को जानकारी मिली है कि हाथरस हादसे के बहाने उत्तर प्रदेश में जातीय दंगा भड़काने के लिए विदेशों से भी करोड़ों का फंड जुटाया गया. इस सूचना के बाद प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय हो गया है. साजिशकर्ताओं के देश-विदेश के कनेक्शनों को खंगालने की तैयारी है. प्रवर्तन निदेशालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच तेज करने का निर्णय लिया है सूत्रों के अनुसार नागरिकता कानून के विरोध में सक्रिय संगठनों ने हाथरस हादसे के बहाने बेवसाइट के जरिए फंड जुटाया ताकि आंदोलन को लंबे समय तक चलाकर उसे हिंसक रूप दिया जा सके. प्रवर्तन निदेशालय की जांच से उन नामों के खुलासे की उम्मीद है जिनके नाम विदेशों और देश के कई हिस्सों से फंड आए. इस बाबत प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू कर दी है. वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित समुदाय की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिन का और समय दिया गया है.

एक और ऐतिहासिक फैसला

“

बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट का 28 साल बाद आया फैसला बहुत महत्वपूर्ण होने के साथ ही विचारणीय भी है। न केवल अपराध शास्त्र, बल्कि विधि शास्त्र के हिसाब से भी इस फैसले का हमारी व्यवस्था पर दूरगामी असर संभव है। सीबीआई कोर्ट के विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी ढांचा ध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी, अर्थात घटना अकस्मात हुई। 351 गवाहों और 600 दस्तावेजी सुबूतों को सुनने-देखने के बाद अदालत के फैसले से साफ है, पेश किए गए सुबूत पर्याप्त नहीं थे, इसलिए सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए। कुल 49 आरोपियों में से 32 ही अभी जीवित हैं, जिनमें से 26 ही अदालत पहुंचे थे। सीबीआई कोर्ट द्वारा बरी किए गए प्रमुख नेताओं, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती इत्यादि ने अवश्य राहत की सांस ली होगी।

बाबरी केस : सभी आरोपी बरी

सीबीआई की विशेष अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल सही कहा कि 06 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा पूर्व नियोजित साजिश के तहत नहीं गिराया गया था। सब कुछ अचानक हुआ था। इसी आधार पर विवादित ढांचा विध्वंस मामलें में माननीय न्यायाधीश ने सभी 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट के आदेश पर संदेह की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल भी यह नहीं चाहता था विवादित ढांचा गिरे। तब की भाजपा अयोध्या विवाद को लम्बे समय तक जीवित रखना चाहती थी, ताकि इस विवाद के सहारे वह हिन्दुत्व का कार्ड खुलकर खेल सके। यही वजह थी विवादित ढांचा गिराए जाने की घटना से भाजपा के दिग्गज नेता सन्न रह गए थे। मुसलमानों का तो कथित बाबरी मस्जिद ढहाए जाने पर गुस्सा स्वाभाविक था, लेकिन उदारवादी हिन्दुओं का बड़ा धड़ा भी इससे बिफर गया था। भाजपा और संघ मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए थे। विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जैसे कुछ दिग्गज नेताओं को सीबीआई ने भले आरोपी बनाया था, परंतु उस समय के भाजपा के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी इस घटना से आहत बताए गए थे। कांग्रेस नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यह बयान देकर कि बाबरी मस्जिद का दोबारा निर्माण कराया जाएगा, भाजपा नेताओं को नया जीवनदान दे दिया।बताया जाता है कि 06 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की खबरें आ रही थीं तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राव पूजा कर रहे थे। दोपहर 1 बजकर 40 मिनट पर बाबरी मस्जिद का पहला गुंबद गिराया जा चुका था। इसके 20 मिनट बाद करीब दो बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास उस समय के केंद्रीय मंत्री और कद्दावर कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार का फोन आया। फोतेदार ने नरसिम्हा राव से कहा, ‘राव साहब, कुछ तो कीजिए, क्या हम फैजाबाद में तैनात वायुसेना के चेतक हेलिकॉप्टर से कारसेवकों पर आंसू गैस के गोले नहीं दगवा सकते हैं? जवाब में नरसिम्हा राव ने सवाल किया, ‘क्या मैं ऐसा कर सकता हूं?’ फोतेदार ने विनती के स्वर में राव से कहा, ‘राव साहब, कम-से-कम एक गुंबद तो बचा लीजिए। ताकि बाद में हम उसे एक शीशे के केबिन में रख सकें और भारत के लोगों को बता सकें कि बाबरी मस्जिद को बचाने की कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। माखनलाल फोतेदार अपनी आत्मकथा ‘द चिनार लीव्स’ में लिखते हैं कि उनके इस सुझाव के जवाब में प्रधानमंत्री चुप रहे। लंबे ठहराव के बाद उन्होंने बुझी हुई आवाज में कहा, ‘फोतेदार जी, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करता हूं। फोतेदार प्रधानमंत्री के रुख से काफी खफा थे। बाबरी मस्जिद का ढांचे गिरने के साथ राव पर आरोपों की झड़ी लग गई थी। खैर, बाबरी मस्जिद ढांचा विध्वंस मामले का फैसला आने के साथ ही प्रभु रामजन्म भूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमों का निस्तारण हो चुका है। बात जहां तक भाजपा की है तो वह कभी नहीं चाहती थी कि विवादित ढांचा गिरे क्योंकि उसकी सियासत के लिए तो ढांचे का खड़ा रहना ज्यादा मुफीद था। बाबरी मस्जिद विवाद का निस्तारण होने के साथ ही अयोध्या में रामजन्मभूमि/बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर अब किसी कोर्ट में कोई मुकदमा पैंडिंग नहीं रह गया है।

कोरोना, लॉकडाउन और बढ़ते मामले

कोरोनाः क्या भारत में धीमी पड़ गयी है संक्रमण की रफ्तार ?

क्या भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम रही है। आंकड़े तो यही कह रहे हैं। अगर हम रोज संक्रमित होने वालों की संख्या को देखें तो सितंबर के मध्य तक यह लगातार और तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अब वह धीरे-धीरे नीचे उतरती दिख रही है। एक समय ऐसा लग रहा था कि हर रोज संक्रमित होने वालों की संख्या एक लाख से ऊपर चली जाएगी लेकिन यह उसके काफी करीब पहुँच कर नीचे आने लग गई। नीचे आने की यह रफ्तार नाटकीय नहीं है इसलिए यह भरोसे के काबिल भी लगती है। लेकिन इसी के साथ यह पहेली भी है क्योंकि संक्रमण इस तरह से नीचे आने लगेगा इसकी उम्मीद तमाम विशेषज्ञों ने भी नहीं बांधी थी। सितंबर के मध्य तक यही कहा जा रहा था कि भारत में कोविड-19 का संक्रमण अभी उस शिखर से बहुत दूर है जहां से ऐसे मामले नीचे आना शुरू कर देते हैं। खासकर बीमारियों के संक्रमण पर नजर रखने वाले सांख्यकीय विशेषज्ञ यह कह रहे थे। वे यह माने बैठे थे कि जैसे-जैसे भारत में कोविड जांच की सुविधा बढ़ेगी ये आंकड़े लगातार बढ़े हुए ही मिलेंगे। जांच की संख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन आंकड़े नीचे आने शुरू हो गए। नए संक्रमित लोगों की संख्या नीचे क्यों आने लगी इसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला कारण सीधा-सा हो सकता है कि संक्रमण अब अपने शिखर पर पंहुच कर नीचे आने लग गया है। हालांकि पूरी दुनिया के अभी तक के आंकड़े देखने के बाद ज्यादातर वैज्ञानिक और स्टेटीशियंस अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके कि इस संक्रमण शिखर का क्या अर्थ लगाया जाए? संक्रमण का शिखर थोड़ा टेढ़ा मामला है, इस पर हम चर्चा थोड़ा बाद में करेंगे। दूसरा मामला कोविड-19 की जांच से जुड़ा है। यह सच है कि पूरे देश में जांच की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है लेकिन हर जगह जांच एक जैसी नहीं है। देश में इसकी जांच दो तरह से हो रही है। एक है आरसी-पीसीआर टेस्ट और दूसरा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। आरसी-पीसीआर काफी महंगा टेस्ट है और इसके नतीजे भी एक दिन बाद मिल पाते हैं, लेकिन यही सबसे भरोसेमंद जांच भी है। इसके मुकाबले रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट काफी सस्ता है और इसके नतीजे भी तुरंत मिलते हैं। लेकिन यह भरोसेमंद नहीं है और कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि इसमें गलती की दर 25 फीसदी तक हो सकती है। पूरे देश में जो टेस्ट बढ़ रहे हैं उनमें ज्यादतर ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ही हो रहे हैं। दिल्ली से एक खबर यह भी है कि यहां आरसी-पीसीआर टेस्ट पहले से कम होने लगे हैं। लेकिन देश भर में आरसी-पीसीआर टेस्ट बहुत कम हो गए हों ऐसी खबर नहीं है, इसलिए अगर आंकड़े कम हो रहे हैं तो इसके लिए जांच के तरीकों को बहुत ज्यादा दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तीसरा कारण हो सकता है आंकड़ों की हेरा-फेरी। यह सच है कि दुनिया के कई देशों से कोरोना संक्रमण के आंकड़े छुपाने और दबाने की खबरें आती रही हैं। यहां तक कहा जाता है कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों तक में सही आंकड़े सामने नहीं आने दिए गए। लेकिन भारत के मामले में इस तरह के प्रमाण या आरोप अभी तक सामने नहीं आए हैं। भारत में अपराध और स्वास्थ्य जैसे मामलों में आंकड़ों को दबाया जाना आम बात मानी जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले में अभी तक इस तरह की बातें सामने नहीं आ सकी हैं। फिर इस समय देश में ऐसे कोई राजनीतिक कारण या दबाव भी नहीं हैं कि आंकड़ों को छुपाने की जरूरत पड़े। लेकिन यहीं पर एक बात को और जोड़ देना जरूरी है कि संक्रमण के मामले

मास्क पर बढ़ता भरोसा

मास्क उस महामारी का सबसे सजीव प्रतीक है, जिससे दुनिया में साढ़े तीन करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हुए और 10 लाख से ज्यादा अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। मास्क पर निरंतर अध्ययन जारी है कि यह कोरोना से बचाव में कितना कारगर है। मास्क के पक्ष में कम से कम आठ शोध सामने आ चुके हैं। एक समस्या यह आ रही है कि दुनिया में तरह-तरह के मास्क या कपड़ों का उपयोग हुआ है, इसलिए मास्क के सुरक्षित कवच होने के संबंध में सुनिश्चित डाटा का अभाव पूरी दुनिया में है। कोरोना का मानक मास्क एन95 को माना जाता है, हवा में रहने वाले 95 प्रतिशत कणों (कम से कम 0.3 माइक्रोमीटर आकार के) को वह शरीर के अंदर नहीं पहुंचने देता है। जब महामारी बढ़ी, तो इन मास्क की कमी हो गई, उसके बाद कपड़े और सर्जिकल मास्क के उपयोग को बढ़ावा देना पड़ा। किस परिवेश में कौन-सा मास्क काम करेगा, यह अभी अध्ययन का विषय है। हालांकि, मास्क किसी भी तरह के हों, सेहत की रक्षा के लिए कमोबेश उपयोगी माने जा रहे हैं। जून में मास्क पर भरोसा इसलिए बढ़ा, क्योंकि अमेरिका में दो हेयर ड्रेसर को कोरोना हुआ। काम करते समय वे दोनों डबल लेयर वाला मास्क पहना करते थे, इसलिए उनके ग्राहक तो बच गए, लेकिन घर वाले संक्रमित हो गए। एकाधिक प्रमाण हैं कि जहां भी मास्क की अवहेलना हुई है, वहां संक्रमण की आशंका बढ़ी है। शोध में यह बात सामने आई है कि जिन इलाकों में लोग मास्क सही ढंग से पहन रहे हैं, वहां मृत्यु दर चार गुणा कम है। शोधकर्ताओं ने 200 देशों के आंकड़ों को खंगालने के बाद बताया है कि मंगोलिया में मास्क को जनवरी के अंत में ही अपना लिया गया था, वहां मई तक कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। अमेरिका में भी जिन राज्यों में अप्रैल-मई में मास्क को अनिवार्य किया गया, वहां कोरोना के मामले प्रतिदिन दो प्रतिशत के हिसाब से घटते चले गए। शोधकर्ताओं का इशारा है कि गणित में मत पड़िए, मास्क अपना काम कर रहा है। हांगकांग में जानवरों पर हुए एक शोध से भी पता चला है कि मास्क की वजह से 75 प्रतिशत जानवर कोरोना से बचे रहे।

अनलॉक 5.0

कोरोना के बीच अनलॉक-5

कोरोना संक्रमण के संकट से जूझ रहे देश में अनलॉक पांच की शुरुआत इस मकसद से हुई है कि जान के साथ जहान बचाना भी जरूरी है। अन्यथा ऐसी स्थितियां अभी बिल्कुल नहीं हैं कि व्यापक छूट दी जा सके। लेकिन हाल में वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी के डराने वाले आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के संग जीना सीखना होगा। अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही विशेषज्ञ देश के कुछ इलाकों में दशहरा-दीवाली के साथ संक्रमण की दूसरी वेब की आशंका भी जता रहे हैं। बहरहाल, संक्रमण के लिहाज से बीता सितंबर माह बेहद बुरा साबित हुआ।

अनलॉक-पांच की प्रक्रिया शुरू करना जहां हमारी मजबूरी है वहीं हमारी चिंता का सबब भी है। जब देश में सिनेमा हॉल और स्कूल खोलने के बात सामने आ रही है तो लोगों व अभिभावकों की चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक है। दरअसल, छह महीने के लॉक़डाउन के चलते जहां देश का फिल्म उद्योग चौपट हो गया है, वहीं बच्चे भी लगातार घर में रहते-रहते उकता गये हैं। घर में बोरियत है तो बाहर जीवन पर संकट का खतरा। दरअसल, इस भयावह महामारी ने ऐसे हालात पैदा कर दिये हैं कि न उगलते बनता है और न ही निगलते। हमारी चिंता तब और बढ़ जाती है जब उत्सवधर्मी देश में दशहरा, दुर्गा पूजा और दीवाली जैसे बड़े त्योहारों का आगमन होने को है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस दौर में ज्यादा संक्रमण की आशंका भी जता रहे हैं। लोग हैं कि हर अनलॉक के साथ लापरवाह होते जा रहे हैं। हालांकि, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में राहत के साथ शर्तों का भी जिक्र है। स्कूल और सिनेमा हॉल खोलने को लेकर स्थिति साफ की गई है। कंटेनमेंट जोन्स को लेकर 31 अक्तूबर तक सख्ती है और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान यथावत है। मार्च से बंद स्कूल-कालेजों को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति तो दी गई है लेकिन इस मामले में अंतिम फैसला राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। साथ ही संक्रमण की दृष्टि से संवेदनशील नाबालिग बच्चों के स्कूल जाने का फैसला अभिभावकों की अनुमति से किया जायेगा। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिये हाजिरी अनिवार्य नहीं की गई है। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल दूरवर्ती शिक्षा व ऑनलाइन पढ़ाई बनी रहेगी। वहीं सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, प्रदर्शनी हॉल व मनोरंजन पार्क कुछ शर्तों के साथ ही खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स में पचास फीसदी सीटें ?खाली रखनी होंगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों व कार्यालयों में मास्क पहनना अभी अनिवार्य ही रहेगा। दो गज की सुरक्षित दूरी बरकरार रखनी होगी। वहीं दफ्तरों में कर्मचारियों को आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य रूप से करना ही होगा। वहीं अनलॉक-पांच में निर्देश दिये गये हैं कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य अपनी सुविधा के लिये गृह मंत्रालय के निर्देशों को लचीला नहीं बना सकते। केंद्र की अनुमति के बिना लॉकडाउन नये सिरे से नहीं लगाया जा सकेगा। अनलॉक-पांच में कुछ शर्तों के साथ सौ से ज्यादा लोगों को एकत्र होने की अनुमति दी जा सकेगी। राज्यों के भीतर व बाहर आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध?अब नहीं रहेगा। साथ?ही घर से काम करने की नीति को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। वहीं लंबे समय से स्वीमिंग पूल खोलने की मांग पर सरकार के निर्देश हैं कि केवल प्रैक्टिस के लिये स्वीमिंग पूल खोले जायेंगे। इस बार में अधिक निर्देश ?खेल मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किये जाएंगे। बुजुर्गों, बच्चों, बीमारों व गर्भवती महिलाओं को अभी भी घर पर ही रहने की सलाह दी गई है।

अनलॉक 5: 15 अक्टूबर से अनलॉक होंगी ये सेवाएं

- सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क
- **शर्त:** कुल क्षमता के 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे
- सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य

कब खुलेंगे स्कूल?

- स्कूल और कोचिंग खोलने के लिए राज्यों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत

उपचुनावों में पूरा दमखम लगा रहे दिग्गज

प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गरम है। भाजपा ने पिछले दस दिनों (2 अक्टूबर गांधी जयंती) से सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में मंडल स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए। इस दौरान भाजपा के सभी बड़े नेता और पदाधिकारी जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य के साथ ही राज्य सरकार के कई मंत्रीयों ने 10 दिन तक मंडल कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। वहीं अब दो दिन के ब्रेक के बाद भाजपा के दिग्गज बूथ स्तर पर जाकर सम्मेलन करने की तैयारी में जुट गए हैं। यह बूथ सम्मेलन 15 अक्टूबर से शुरू होंगे और 25 अक्टूबर तक चलेंगे। बूथ सम्मेलनों को विजय संकल्प के रूप में मनाया जाएगा। इनके जरिए जिन क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति कमजोर है उन क्षेत्रों में वोटरों को रिझाने संगठन स्तर पर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही इन बूथों में नियुक्त किए गए बूथ संयोजक, पन्ना प्रभारी व बूथ अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों को उत्साहित करने का काम भी किया जाएगा।

इसमें खास बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित पार्टी के तमाम दिग्गज भी इन सम्मेलनों के जरिए बूथ स्तर तक कसावट का काम करेंगे। भाजपा द्वारा 28 विधानसभा सीटों पर मंडल स्तर पर आयोजित किए गए सम्मेलनों का आज अंतिम दिन है। इन सम्मेलनों के जरिए सभी नेता हर रोज 2 से 3 मंडलों में पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक और सभाएं ले रहे थे। अब पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति ने 2 दिन का ब्रेक देने के बाद बूथ सम्मेलन की तैयारी तेज कर दी है। भाजपा के यह बूथ सम्मेलन उपचुनाव वाली सभी 28 विधानसभा सीटों पर 15 से 25 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इन सम्मेलनों की जिम्मेदारी जिला स्तर के पदाधिकारियों विधायकों को ही सौंपी जाना है। सांसद, विधायक, मोर्चा व संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष, जिलों के पदाधिकारी ही इन सम्मेलनों के जरिए बूथ कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। प्रदेश की उपचुनाव वाली सभी 28 विधानसभा सीटों पर नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। चूंकि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इस बार नामांकन के दौरान रैली और समर्थकों की संख्या को लेकर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इसे देखते हुए सभी उम्मीदवार अपनी सुविधा से अलग-अलग फार्म जमा कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्थानों पर नामांकन के बाद बूथ सम्मेलनों में पार्टी के दिग्गज नेता पहुंच सकते हैं। वहीं, बूथ सम्मेलनों के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में नेताओं की सभाएं भी रखी जा सकती हैं।भाजपा ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों पर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती है।

कांग्रेस की रायसेन में चुनावी सभा:कमलनाथ ने कहा-

प्रदेश की जनता हमारी नीति और नीयत जानती है; हमने मिलावट और माफिया के खिलाफ अभियान चलाया

कांग्रेस प्रत्याशी मदनलाल चौधरी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता हमारी नीति और नीयत जानती है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से लोकतांत्रिक सरकार गिराकर उपचुनाव होगा। हमने 15 महीने की सरकार में ही अपनी नीयत का परिचय दिया है। मिलावट और माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। गौ शालाएं बनवाई। लाखों किसानों का कर्जमाफ किया। वे बोले- मैं कमलनाथ हूं, शिवराज नहीं। 15 साल का हिसाब नहीं देते, 15 महीने का हिसाब मांगते हैं। इसलिए आप आम लोगों के बीच सीना तानकर जाएं। सभा को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी संबोधित किया। सांची विधानसभा सीट के लिए होने वाले उप चुनाव के लिए मंगलवार से आचार संहिता लागू हो गई है। इस बार यह चुनाव कोविड-19 की गाइड लाइन को ध्यान में रखकर ही कराए जाएंगे। मतदान केंद्र पर भीड़ की स्थिति न बने, इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 39 मतदान केंद्र बढ़ाए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1000 मतदाताओं तक की संख्या सीमित कर दी गई है । इतना ही नहीं वोट डालने के लिए आने वाले मतदाताओं को ग्लब्स पहनकर ही ईवीएम का बटन दबाना होगा। ग्लब्स और मास्क की व्यवस्था केंद्र पर प्रशासन द्वारा की जाएगी। बुजुर्ग और कोरोना के मरीज डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे। यह व्यवस्था भी पहली बार निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है ।

नाथ को है विश्वास 18 सीटें भी ले आए तो बनेंगे मुख्यमंत्री

सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को विश्वास है कि जनता में सहानुभूति है। वह इस बात को समझेगी की सिंधिया ने गद्दारी करके सरकार गिराई। यही वजह है कि प्रदेश में उपचुनाव की स्थिति बनी। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि उपचुनाव में कांग्रेस यदि 18 सीटें भी जीतती है तो सत्ता में वापसी की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि उपचुनाव के नजदीक आते-आते राजनितिक पंडितों के कयास और सूत्र भी बेहद सक्रिय हो चुके हैं। कमलनाथ जहाँ 15 महीनों की उपलब्धियों और सुशासन को भुनाने की जुगत में हैं। यही कारण है कि कांग्रेस में उपचुनाव की कमान पूरी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने संभाल रखी है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारी मशीनरी, धनबल और कोरी घोषणाओं के सहारे उपचुनाव जीतना चाहते हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा का संगठन मजबूत माना जाता है। बीजेपी को अपने संगठन, सत्ता के साथ-साथ संघ की ताकत पर पूरा भरोसा है। जानकारों का मानना है कि उपचुनावों में भाजपा सिर्फ आठ सीट जीतकर भी सरकार बचा लेगी। परन्तु राजनीतिक पंडित की राय यह भी है कि भाजपा को अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस से अधिक सीट जीतना ही पड़ेगी। जिस तरह से कमलनाथ ने उम्मीदवारों का चयन किया है, वह भी एक लम्बी प्लानिंग की तरफ इंगित करता है।

बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर

सुशांत केस में अब ड्रग एंगल की एंट्री

बॉलीवुड में नशे के किस्से नये नहीं हैं। जब तब नशीली पार्टियों व रेव पार्टियों की खबरें आती रही हैं। मायानगरी की चकाचौंध और निरंकुश जीवन व्यवहार इसके मूल में रहा है। अथाह पैसा और ग्लैमर का गुमान भी वैसे नशे से कम नहीं होता। कई रहस्यमय हत्याओं व आत्महत्याओं से नशे के तार जुड़ते रहे हैं। युवा सितारे सुशांत राजपूत की रहस्यमय मौत के घटनाक्रम ने पूरे देश को उद्वेलित किया। जमकर राजनीति भी हुई और टीआरपी का निर्लज्ज खेल भी। फिर अचानक कैमरा नशे के संजाल की तरफ मुड़ गया या यूं कहें मोड़ दिया गया। सवाल उठने लगे कि सुशांत कांड से पर्दा उठाने का दायित्व सीबीआई को सौंपा गया था तो कहानी में अचानक नशे का ट्विस्ट कैसे आ गया?

अब सुशांत कांड तो पार्श्व में चला गया और नशे के बुलबुले फूटने लगे। सवाल यह ?भी कि सीबीआई सुशांत मामले की जांच में कहां तक पहुंची है? क्यों इस मामले से ध्यान हटाकर

सिने-तारिकाओं को एनसीबी के समन देने की ओर केंद्रित हो गया? यह अच्छी बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशे के संजाल से आवरण हटाने का प्रयास कर रहा है मगर सामने जो लोग आ रहे हैं, वे तो छोटी मछलियां हैं। एनसीबी की सफलता तब मानी जायेगी जब नशे के कारोबार के असली खिलाड़ियों के गिरेबान तक हाथ पहुंचेगा। जब तक इस खेल के असली खिलाड़ी बेनकाब नहीं होंगे तब तक नशे का संजाल उलझता ही रहेगा। इस प्रकरण से जुड़ी छोटी-बड़ी खबरों का कार्रवाई से पहले बाहर आना और इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा जोरदार ढंग से इसे प्रचारित करना भी चौंकाता है।?ऐसे वक्त में जब कोविड संकट भयावह स्थिति में है और चीन एलएसी पर देश की सेना को उलझाये हुए है तो बॉलीवुड के नशे को इतना महत्व देने का आखिर क्या औचित्य है? कृषि सुधार और उससे जुड़े विरोध को कोई तार्किक दिशा देने की भी कोई गंभीर कोशिश होती नजर नहीं आई। निस्संदेह यह गैरजिम्मेदार व्यवहार हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। निस्संदेह बॉलीवुड में नशे की दलदल का गहरा होना हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। इसकी एक वजह यह भी है कि देश में करोड़ों युवा इन अभिनेताओं-अभिनेत्रियों को अपने जीवन का नायक मानते हैं। जाहिरा तौर पर इनके नशे में लिप्त होने का समाज में गलत संदेश जायेगा लेकिन समाज में नशे के बढ़ते प्रकोप का परिदृश्य और भयावह है। 'उड़ता पंजाब' में पंजाब में नशे के भयावह प्रसार का चित्र उकेरा गया था?लेकिन मौजूदा हालात में तो पूरा देश उड़ता नजर आ रहा है। इसी सप्ताह संसद में बताया गया कि देश के डेढ़ करोड़ बच्चे नशे की लत का शिकार हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कुछ वर्ष पूर्व देशभर में कराये गये सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि देश में 10 से 17 वर्ष के अनुमानित चालीस लाख बच्चे और किशोर अफीम का नशा कर रहे हैं। अनुमानित पचास लाख बच्चे सूंघकर या कश के जरिये लिये जाने वाले नशे का सेवन कर रहे हैं। दो लाख बच्चे कोकीन और चार लाख बच्चे उत्तेजना पैदा करने वाले नशीले पदार्थ लेते हैं। सर्वे का निष्कर्ष बताता है कि हमारे आसपास करीब 1.48 करोड़ बच्चे एवं किशोर अल्कोहल, अफीम, कोकीन व भांग आदि के नशे का सेवन कर रहे हैं। बॉलीवुड ही क्यों, हमारे आसपास नशे के सेवन से जो स्थिति पैदा हो रही है, वह भयावह है। इतना ही नहीं, नशे की यह लत समाज में गंभीर अपराधों को भी जन्म देती है। नशे की लत पूरी करने के लिये जब पैसे नहीं जुटते तो वे चोरी-लूट की वारदातों में लिप्त पाये जाते हैं। नशा किशोरों के व्यवहार में आक्रामकता ला रहा है, जो हमारी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। कमोबेश यही स्थिति शराब के बढ़ते सेवन को लेकर भी है। सर्वे बताता है कि 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग में शराब का सेवन करने वालों की संख्या 15.10 करोड़ है। हर खुशी और गम में बोतल खोलने की प्रवृत्ति को इस बढ़ते संकट के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

ड्रग स्कैंडल में फंसे बड़े-बड़े

एनसीबी की राडार में आयी 50 से अधिक फिल्मी हस्तियां

सुशांत का पूरा मामला अब बॉलीवुड और ड्रग्स के कनेक्शन पर आकर ठहर गया है. मामले में जांच कर रही रोजाना बड़े-बड़े बॉलीवुड कलाकारों से पूछताछ कर रही है. ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां राडार पर हैं. ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भी बुरी तरह से फंस चुकी हैं.बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से हुई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत सिंह के बैंक खातों से हुए लेन-देन की जांच करेगा।

बॉलीवुड सेलेब्स के बयान और गिरफ्तारी पर चर्चा हुई। इस दौरान अस्थाना ने टीम को निर्देशित किया कि इस केस में चार्जशीट फाइल करने के लिए 6 महीने का वक्त है। इसलिए पहले सबूतों का रिव्यू किया जाएगा।सूत्रों की मानें तो एनसीबी ने अब तक जितने भी सेलेब्स से पूछताछ की है, उनमें से किसी को भी फिलहाल क्लीन चिट नहीं दी गई है। इसके अलावा 20 हाई प्रोफाइल ड्रग पैडलर जांच एजेंसी की राडार पर हैं। डेटा का बैकअप लेने के लिए श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और दीपिका पादुकोण के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैंएनसीबी की मीटिंग में करन जौहर की पार्टी के वायरल वीडियो पर भी चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कि वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच एजेंसी को मिल गई है और इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि वीडियो एकदम सही है, इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। दावा किया जा रहा है कि 2019 में करन जौहर के घर हुई इस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, करन कई बार इस बात से इनकार कर चुके हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा था, मैं न तो ड्रग्स लेता हूं और न ही इसे प्रमोट करता हूं। मेरे और मेरे परिवार के बारे में, साथियों और धर्मा प्रोडक्शन के बारे में जो बातें की जा रही हैं, वे बकवास हैं। बताया जा रहा है कि सारा और श्रद्धा ने पूछताछ में कहा था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। इनसे पहले रकुलप्रीत सिंह ने रिया से ड्रग्स के बारे में चैट करना कबूल किया था। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा, कुक दीपेश सावंत और ड्रग पैडलर बासित परिहार की जमानत पर भी फैसला आ सकता है। इन सभी की अर्जियां लोअर कोर्ट्स से 2-2 बार खारिज हो चुकी हैं।

भारतीय राजनीति का बड़ा सितारा हुआ अस्त

रामविलास पासवान के रूप में भारतीय राजनीति का और बड़ा दलित सितारा 'बुझ' गया। बिहार में पिछले आधे दशक से बाबू जगजीवन राम के बाद यदि कोई दलित चेहरा चमकता रहा, वो रामविलास पासवान ही थे। संयोग देखिए जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण को रामविलास पासवान अपना आदर्श मानते थे, उन्हीं की 41वीं पुण्यतिथि पर पासवान ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राम विलास पासवान दलित राजनीति की वह धुरी थे, जिसके इर्दगिर्द देश की राजनीति घूमा करती थी। करीब आधे दशक के सियासी सफर में पासवान %न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर' की लाइन पर ही चलते रहे। दलितों का हित साधने के लिए उन्होंने कभी भी किसी सरकार से निकटता बढ़ाने में परहेज नहीं किया। पासवान को जब भी केंद्र में मंत्री पद मिला, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम जरूर किया जो देशव्यापी चर्चा में जरूर रहा है। पहली बार छह दिसम्बर 89 को वह प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के मंत्रिपरिषद में श्रम व कल्याण मंत्री बने थे। कम लोगों को पता होगा कि इस दौरान वो समाज कल्याण मंत्री थे, जिसके चलते उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को देश में लागू करने का काम किया था। इसके चलते ओबीसी समुदाय के 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिला, जिससे देश की राजनीति बदल गई थी।

देश के कद्दावर दलित नेताओं की जब चर्चा होती है तो उसमें संविधान निर्माता बाबा साहब भीमरामराव अम्बेडकर के बाद जो चंद नाम लिए जाते हैं उसमें बाबू जगजीवन राम, मान्यवर कांशीराम, मायावती, रामदास अठावले, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भोलानाथ पासवान आदि कुछ बड़े नेताओं के साथ रामविलास पासवान का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। इन सब नेताओं की राजनीति करने की शैली भले अलग-अलग रही हो, लेकिन अंत में सब दलित हित की बात सोचा करते थे।ऐसा नहीं है कि उक्त दलित नेताओं के अलावा देश में कोई दलित चेहरा सामने ही नहीं आया। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उदित राज, युवा दलित नेता चिराग पासवान, चन्द्रशेखर आजाद 'रावण' जैसे तमाम नाम गिनाए जा सकते हैं, लेकिन यह कभी खालिस दलित नेता नहीं बन सके। इसकी वजह है सामाजिक रूप से दलित समाज का बेहद पिछड़ा हुआ होना।

दलित नेताओं की कमी के चहते ही अक्सर उनकी (दलितों की) समस्याओं/उत्पीड़न के मामलों पर कार्रवाई की बजाए दलितों के हिस्से में सिर्फ सियासत हाथ आती है, जो नेता दलितों के हितों की बात करते भी हैं उनकी सोच दलितों के भले से अधिक अपने सियासी नफा-नुकसान पर रहती है। यही वजह है कि आज भी दलितों की स्थिति में आमूल-चूल बदलाव ही हो पाए हैं। दलितों के मसीहा बनकर उनके नाम पर सत्ता हासिल करने वालों की लम्बी लिस्ट है पर दलितों के लिए काम करने वालों के नामों की लिस्ट बनाने की कभी जरूरत ही नहीं समझी गई, क्योंकि इनकी संख्या इतनी कम है कि इनके नाम

उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं। 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में दलितों की जनसंख्या करीब 22 प्रतिशत है लेकिन इनके नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं की संख्या 100 प्रतिशत है। कांग्रेस, भाजपा या अन्य दलों का चुनाव के समय जिस तेजी से दलित प्रेम जागता है, चुनाव के बाद उतनी ही तेजी से वह 'सो' भी जाता है। सही मायनों में दलितों के हित में बात करने वालो में और उनके लिए काम करने वालों नेता अब बचे ही नहीं हैं। दलितों में अलख जगाने का सबसे अधिक काम डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने किया था। अगर डॉ. अम्बेडकर नहीं होते तो आज दलितों की जो स्थिति है, उससे भी बदत्तर होती। डॉ. अम्बेडकर ने जब दलितों के लिए आरक्षण और अलग चुनाव प्रणाली की मांग की थी तब उनकी यह मांग नहीं मानी गयी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की धमकी दी वैसे ही उनकी यह मांग मान ली गई और पूना पैक्ट समझौता हो गया। पूना पैक्ट समझौते के कारण दलितों को बहुत लाभ मिला हालांकि उन्हें पूरा आरक्षण नहीं मिल सका, लेकिन कम से कम आधा-अधूरा आरक्षण तो मिल ही गया था। इस समझौते के कारण ही दलितों के लिए शिक्षा के लिए दरवाजे खुल गए। आजादी से करीब 17 वर्ष पूर्व 1929-1930 के अपने एक बयान में डॉ. अम्बेडकर ने गांधी जी से कहा था, %मैं सारे देश की आजादी की लड़ाई के साथ उन एक चौथाई जनता के लिए भी लड़ना चाहता हूँ जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आजादी की लड़ाई में सारा देश एक है और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, वह सारे देश के खिलाफ है, मेरी लड़ाई बहुत कठिन है। यह और बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद उनके कई अनुयायी दलितों के हक की लड़ाई जारी रखने के लिए सामने आए पर उन्होंने दलितों की लड़ाई के नाम पर गठित की डॉ. अम्बेडकर की पार्टी को खुद की ही लड़ाई की भेंट चढ़ा दिया। डॉ. अम्बेडकर द्वारा खड़ी की गई रिपब्लिक पार्टी बाद के दिनों में 4 भागों में बंट गई। एक भाग रामदास अठावले के नेतृत्व में पहले शिवसेना में फिर बाद में भाजपा में शामिल हो गया। डॉ. अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में शामिल हो गए। एक भाग जिसमें योगेंद्र कबाडे थे वे भी बाद में भाजपा में शामिल हो गए।

108 करोड़ रूपये की लागत से बने डेढ़ कि.मी. लम्बे फ्लाई ओवर का लोकार्पण सम्पन्न

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से प्रदेश में विकास-गाथा लिखी जा रही है। इस विकास-गाथा में नित नये अध्याय जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान मुरैना में 108 करोड़ रूपये की लागत से बने 1.5 कि.मी. लम्बे फ्लाई ओवर के लोकार्पण कार्यक्रम को भोपाल से वेबकास्ट पर संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय कृषि तथा पंचायत राज ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर मुरैना में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल व्ही.के. सिंह, केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते तथा राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम में डिजिटल सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने फ्लाई ओवर के लिये केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी और केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि फ्लाई ओवर के निर्माण से मुरैना में आवागमन सुविधाजनक होगा।

आज मुरैना के विकास में एक नया अध्याय जुड़ा है। मुख्यमंत्री श्री सिंह ने कहा कि मुरैना को नगर निगम बनाने, अस्पताल तथा कलेक्ट्रेट भवन निर्माण, सड़क नेटवर्क व सिंचाई सुविधा के विस्तार जैसी गतिविधियों से क्षेत्र प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। भिण्ड में सैनिक स्कूल और मुरैना में चंबल से पानी लाने की दिशा में भी कार्य जारी है। विकास गतिविधियां निरंतर जारी रहेंगी। मुरैना देश में अपनी विशेष पहचान बनाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर में दिव्यांग परिसर के लिये केन्द्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत को धन्यवाद दिया।

सहकारिता मंत्री ने वितरित किए वनाधिकार प्रमाण-पत्र

शिवपुरी। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत शनिवार को प्रदेश में वनाधिकार उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही शिवपुरी जिले में भी वनाधिकार उत्सव मनाया गया। जिला एवं जनपद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर वनाधिकार पट्टे वितरित किये गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के संवाद का लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से प्रसारण भी किया गया। जिसे कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण एवं हितग्राहियों ने सुना।जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया के आतिथ्य में संपन्न हुआ। जिसमें उन्होंने 25 हितग्राहियों को वनाधिकार प्रमाण पत्र प्रदाय किए। इसके लिए हितग्राहियों ने भी उनका आभार व्यक्त किया। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासी परिवारों की चिंता कर वर्षों से निवासरत भूमि का मालिकाना हक प्रदान कर उन्हें वन भूमि के अधिकार पत्र प्रदाय किए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आज जिले में सहरिया जनजाति समुदाय के 104 व्यक्तियों को हक प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया हैं। कार्यक्रम में विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, पूर्व विधायक प्रहलाद भारती, सांसद प्रतिनिधि हेमंत ओझा, अन्य जनप्रतिनिधिगण, लाभांवित हितग्राहियों सहित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व प्रभारी कलेक्टर एच.पी.वर्मा, डीएफओ लवित भारती, डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी आदिम जाति कल्याण विभाग शिवांगी अग्रवाल उपस्थित थे।

प्रदेश सरकार गरीब एवं असहायों तक सहायता पहुँचाने के लिये कटिबद्ध

ग्वालियर गृह, जेल एवं विधि विधायी कार्य मंत्री डॉण् नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार गरीब, असहाय एवं अन्य जरूरतमंदों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाने के लिये कटिबद्ध है। समाज में प्रताड़ित हुए लोगों को भी सरकार तत्परता से राहत मुहैया करा

रही हैए जिससे ये लोग फिर से सम्मानपूर्वक सामाजिक एवं मानसिक रूप से खड़े हो सकें। डॉण् मिश्र रविवार की शाम ग्वालियर कलेक्ट्रेट में पीड़ित परिवारों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत राशि का वितरण कर रहे थे। ग्वालियर जिले के 46 पीड़ित परिवारों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत लगभग 71लाख 63 हज़ार रुपये की राशि मंजूर हुई है। गृहमंत्री डॉण् मिश्र ने इनमें से 16 पीड़ित परिवारों की मौजूदगी में कम्प्यूटर से सिंगल क्लिक के जरिए उनके बैंक खातों में कुल 37 लाख 12 हजार 500 रूपए की राहत राशि पहुँचाई। साथ ही इन परिवारों को स्वीकृत राशि के प्रमाण.पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक अविनाश शर्मा, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रमसिंह, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एचबी शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं राहत प्राप्त करने वाले परिवारों के सदस्यगण मौजूद थे।

प्रदेश सरकार ने बाबा साहब के विचारों पर चलकर गरीबों के कल्याण के लिये योजनाएं बनाई

ग्वालियर। प्रदेश के साथ आज ग्वालियर में भी 'अन्न उत्सव' मनाया गया। यहां बाल भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और पूर्व विधायक ने प्रतीक स्वरूप लगभग दो दर्जन हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची एवं राशन किट प्रदान कर जिले में अन्न उत्सव का शुभारंभ किया। सांसद शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलकर गरीबों के कल्याण के लिये योजनाएं बनाई हैं। अभियान के तहत जिलेभर में 21 हजार 126 नए हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची एवं राशन किट वितरित की गईं। इन सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक रूपए प्रतिकिलो गेहूं अथवा चावल, एक रूपए लीटर केरोसीन तथा एक रूपए प्रतिकिलो के हिसाब से चना (दाल) मिलना शुरू हो गई है। श्री शर्मा ने कहा कि देश का समग्र विकास तभी संभव है जब गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को भलीभांति समझा है। इसीलिए केन्द्र व राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा देने एवं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये तमाम कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं। कार्यक्रम में जयप्रकाश राजौरिया, लोकेन्द्र पाराशर व कमल माखीजानी सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह मंचासीन थे।

मेहगांव में आत्मनिर्भर भारत कृषक सहकारी सम्मेलन आयोजित

मेहगांव में कृषि उपजमंडी मेहगांव में आत्मनिर्भर भारत कृषक सहकारी सम्मेलन आयोजित किया गया सम्मेलन में मेहगांव गोहद गोरमी अमायन मो के किसान मौजूद थे। राज्यमंत्री ओपीएस भदौरिया सांसद संध्या राय जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर ने भी संबोधित किया। प्रदेश के सहकारिता एवं लोकसेवा प्रवंधन मंत्री अरबिंद सिंह भदौरिया ने कहा, कि जबतक देश का किसान आत्मनिर्भर नही होगा तबतक आत्मनिर्भर भारत सम्भव नही मंत्री श्री भदौरिया कृषि उपजमंडी मेहगांव में आत्मनिर्भर भारत कृषक सहकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष संजीब कांकर पूर्व विधायक मुकेश चौधरी, बरिष्ठ नेता अशोक भारद्वाज, केपी सिंह भदौरिया, जिला महामंत्री सतेन्द्र भदौरिया, पूर्व मंडी अध्यक्ष देवेन्द्र नरवरिया, केदार वर्मा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सीमा शर्मा, मेहगांव

नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष ममता भदौरिया, केशव सिंह भदौरिया, कोक सिंह नरवरिया, मण्डल अध्यक्ष गजेंद्र भदौरिया, सुभाष थापक, जेल सिंह नरवरिया, राजबीर गुर्जर, अबधेश बधेल, रमन सिंह भदौरिया, गुरुदेव नरवरिया, धीरसिंह भदौरिया, बबली तोमर, बेबी राठौर, अजय सिंह भदौरिया, सत्यभान नरवरिया आदि जन मंचासीन थे।

डॉ.सिकरवार का जगह-जगह हुआ पुष्पवर्षा कर स्वागत

ग्वालियर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. सतीशसिंह सिकरवार ने 16 ग्वालियर पूर्व विधानसभा के नाकाचन्द्रवदनी क्षेत्र में शनिवार की सुबह सैकड़ो कार्यकर्ताओं के साथ घर-घर जाकर जनसम्पर्क किया। नाकाचन्द्रवदनी क्षेत्र में जनता द्वारा जगह-जगह डॉ. सिकरवार का पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। सैकड़ो कार्यकर्ताओं की भीड द्वारा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाये जा रहे थे। आज सुबह करीब 8 बजे सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ता डॉ. सतीष सिंह सिकरवार के

नेतृत्व में नाकाचन्द्रवदनी तिराहा पर एकत्रित हुये और वहां से डॉ. सिकरवार के साथ पुरूवियों मौहल्ला, गली नं.1, गली नं.2, गली नं.3, गली नं.4 से मुडिया पहाड शंकर चौक होते हुये नाकाचन्द्रवदनी क्षेत्र की विभिन्न गलियों एवं मौहल्लों में जनसम्पर्क किया।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये सभी व्यवस्थायें बेहतर ढंग से की जाएंगी

ग्वालियर-विधानसभा उप निर्वाचन-2020 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय बॉर्डर समन्वय की बैठक आशीष सक्सेना एवं आईजी ग्वालियर रेंज श्री अविनाश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को स्मार्ट सिटी कंट्रोल कमांड सेंटर से की। बैठक में शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ललितपुर, झांसी एवं बारा जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ-साथ झाँसी के आईजी भी शामिल हुए। संभागीय आयुक्त श्री सक्सेना ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार बॉर्डर समन्वय की बैठक कोविड-19 के कारण ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही है। उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान के कई क्षेत्र प्रदेश में उपचुनाव वाले संबंधित जिलों से लगे हुए हैं। इन क्षेत्रों में भी आदर्श आचार संहिता के तहत आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है। शिवपुरी, अशोकनगर एवं गुना जिले की सीमाओं से उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान लगा हुआ है। झाँसी, बारा एवं ललितपुर पर चैक पोस्ट स्थापित किए जाना है। इसके साथ ही लगे हुए क्षेत्रों में अवैध हथियारों के संबंध में कार्रवाई अपेक्षित है। संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने यह भी कहा कि बॉर्डर पर चैक पोस्ट स्थापित कर दोनों प्रदेश के पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से चैकिंग करें यह भी सुनिश्चित किया जाना है। उन्होंने अपेक्षा की कि गत निर्वाचनों की तरह इस निर्वाचन में भी आपसी समन्वय के साथ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिये सभी व्यवस्थायें बेहतर ढंग से की जायेंगीं। आईजी ग्वालियर रेंज श्री अविनाश शर्मा ने भी झाँसी के आईजी एवं ललितपुर, झाँसी और बारा के पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर पुलिस के माध्यम से की जाने वाली व्यवस्थाओं को तत्काल प्रारंभ करने की बात कही। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान से अवैध शराब के कारोबार करने वालों के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई करने की अपेक्षा भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ग्वालियर से संयुक्त उपायुक्त राजस्व श्री आर पी भारती, सीईओ स्मार्ट सिटी श्रीमती जयति सिंह एवं संभागीय समन्वय अधिकारी श्री तोमर भी उपस्थित थे।

आवश्यकता है

पुष्पांजली टुडे राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका/ऑनलाइन न्यूज पोर्टल को भारत के हर राज्य, जिला एवं तहसील स्तर पर ब्यूरो चीफ, रिपोर्टर और विज्ञापन प्रतिनिधियों की आवश्यकता है।
इच्छुक एवं अनुभवी व्यक्ति संपर्क करें।

कार्यालयः ए-ब्लॉक 404 भाऊ साहब की पोतनिस, इन्क्लेव मुरार रोड गोले का मंदिर ग्वालियर
संपर्कः 7999246560,
8269307478
Email-pushpanjalitoday@gmail.com.
Web-www.pushpanjalitoday.com

ग्वालियर जिले की तीन विधानसभा के लिये चुनाव होगा

ग्वालियर। मध्यप्रदेश में होने वाले उप चुनावों की घोषणा के साथ ही जहां आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहीं उप चुनावों को लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी करना शुरू कर दी है। उप चुनावों के लिये 9 अक्टूबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं कोविड को लेकर कई तैयारियां भी अलग से उप चुनावों में चुनाव आयोग के परिपालन में की जा रहीं है। उक्त जानकारी पत्रकारों को देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि ग्वालियर जिले की तीन विधानसभा के लिये चुनाव होगा। इसके लिये जहां ग्रामीण क्षेत्र में डबरा और भितरवार और शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 16 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। 17 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 19 अक्टूबर को नाम वापस हो सकेंगे। मतदान तीन नवंबर को होगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि उप चुनावों में 01-01-2020 को आधार मानकर मतदाता वोट डाल सकेंगे। ईवीएम भी 300 प्रतिशत एक्सिस हैं। वोट वोटर कार्ड को प्राथमिकता के आधार पर डाले जा सकेंगे वहीं वोटर कार्ड नहीं होने पर 11 अन्य दस्तावेजों से वोट डाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड को देखते हुये पूरी प्रक्रिया के दौरान मास्क लगाना होगा। साथ ही सेनेटाइजेशन भी जरूरी होगा। इसके लिये अलग से हेल्थ अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। चुनाव में प्रत्याशी ऑन लाइन भी फार्म भर सकेंगे। वहीं दो लोगों के साथ निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। मतदान केन्द्रों पर एक हजार मतदाता ही मतदान करसकेंगे। वहीं अधिक होने पर मतदान केन्द्र की संख्या बढाई जायेगी। मतदान पार्टी को तीन दिन पहले बता दिया जायेगा कि उन्हें कहां मतदान कराने जाना है। कोविड को देखते हुये 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। मतगणना स्थल एमएलबी के ए ब्लॉक को लेने के लिये शासन की तरफ से पत्र भेज दिया गया है। जनसभा के लिए भी स्थान चयनित कर लिये हैं।

जनसभाएं चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुसार होंगी। मतदान के लिए 1188 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। कलेक्टर ने बताया कि ग्वालियर के तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में 8,30,630 मतदाता वोट का उपयोग कर सकेंगे। इनमें 15 ग्वालियर में 2,88,81 वोटर , ग्वालियर पूर्व में 3,14,511 तथा डबरा में 2,28,011 वोटर वोट कर सकेंगे। पत्रकार वार्ता में एडीशनल कलेक्टर आशीष तिवारी, एडीएम किशोर कान्याल भी मौजूद थे।

उपचुनाव को लेकर एसपी अमित सांघी ने अफसरों को एक्शन मोड में आने को कहा, एक भी गुंडा बाहर न दिखे

लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगीः पुलिस अधीक्षक

ग्वालियर. जिले की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक ने अफसरों को एक्शन मोड में आने के लिए कहा है। एसपी अमित सांघी ने क्राइम समीक्षा बैठक में पुलिस अफसरों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक भी गुंडा, बदमाश बाहर न दिखे। वारंटियों, निगरानीशुदा बदमाशों को पकड़कर जेल भेजा जाए। थानों में हथियार जमा की प्रक्रिया पर सख्ती से काम किया जाए। बैठक में एएसपी पंकज पाण्डे, सत्येन्द्र सिंह तोमर, सुमन सिंह गुर्जर के साथ ही सभी सीएसपी व थाना प्रभारी मौजूद रहे साथ ही एसपी ने कहा कि आचार संहिता चाहे कुछ दिन बाद लगनी हो पर आप सभी चुनावी मोड पर आ जाओ। नशा सामग्री की तस्करी करने वालों पर अंकुश लगाए शराब, स्मैक, गांजा व अन्य नशा सामग्री की तस्करी करने वालों की सूची बनाकर उन पर अंकुश लगाए। इसके अलावा हथियारों की तस्करी पर कड़ी नजर रखकर कार्रवाई करते रहें। जिले की सीमा में किसी भी हालत में यह तस्कर सक्रिय न रह पाएं। पीड़ितों के मामले में गंभीरता से कार्रवाई करने की बात कही एसपी अमित सांघी ने बैठक में थाना आने वाले पीड़ितों और उनके मामले में सुनवाई पर गंभीरता से कार्रवाई करने की बात कही है। साफ शब्दों में कहा है कि लापरवाही बर्दाशत नहीं की जाएगी।

कोरोना काल और बढ़ती हुई बेरोजगारी

योगेश शर्मा

आज के समय में शिक्षित नवयुवकों के लिए बेरोजगार होना किसी दंश से कम नहीं है और ऐसे समय में अगर कोई महामारी व्यापक रूप में संलयित हो जाए तो क्या कहना,मानो एक कहावत चरितार्थ हो गई हो, करेला और नीम चढ़ा। बीते 6 महीनों से लेकर वर्तमान समय तक कोरोना वायरस के प्रसार के कारण लगभग प्रति सप्ताह किसी ना किसी क्षेत्र में हजारों शिक्षित,भविष्य के सपने संजोए युवाओं को या तो अपने रोजगार,नौकरी से हाथ धोना पड़ा या कई युवा पिछले 6-7 महीनों से रोजगार के इंतजार में पलकें बिछाए बैठे हैं। जो युवा निजी संस्थानों में कार्यरत थे,उनमें से भी कई लोगों को निकाल दिया गया। कई लोगों के वेतन में भारी कटौती भी की गई। मॉल्स, रेस्तरां,बार,होटल सब बंद है। विमान सेवाएं और अन्य आवाजाही के सभी साधन बंद कर दिए गए। जिससे युवा उद्धमी और युवा कर्मचारी की तो जैसे रीड की हड्डी ही टूट सी गई। फैक्ट्री कारखाने भी बंद कर दिए गए,संस्थान लगातार लोगों की कटौती करने लगे। जिससे हर कोई आज भी इस डर के साए में जी रहा है कि ना जाने कब उसकी नौकरी जाती रहे। इसके अलावा स्वरोजगार में लगे लोग,चिते मोटे काम धंधे करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई काम धंधा या

आय का कोई स्त्रोत नहीं बचा है।बोस्टन कॉलेज के काउंसलिंग मनोविज्ञान के प्रोफेसर और द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क इन एज ऑफ अंसर्टेनिटी किताब के लेखक डेविड ब्लूस्टेंन का कहना है, बेरोजगारी की वैश्विक महामारी आने वाली है, अतः मैं इसे संकट के भीतर का संकट कहता हूं। जिन लोगों की नौकरियां अचानक से चालू गईं या जी युवाओं के रोजगार अचानक बंद हो गए हैं,उन्हें आर्थिक संकट के साथ साथ मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।सरकारों,स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता की है रही है,किन्तु प्रश्न यह भी है कि नौकरी जाने या रोजगार का स्त्रोत बंद होने पर अपनी भावनाओं को ये युवा कैसे संभाले,जिनके सपने चूर चूर हो गए हैं। ये युवा ऐसा क्या करें जिससे नकारात्मक भावनाएं खुद पर हावी ना होने पाएं? कुछ शिक्षित युवा जो होटल या बार में काम करते थे वे भी महामारी के कारण बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी के कारण दर दर भटक युवा अब शासन से बित्तिय सहायता और चैरिटेबल संस्थाओं से आश लगा रहे हैं कि काश ! उन्हें कोई मदद मिले।एक सर्वे के अनुसार नौकरी जाने का मानसिक तनाव व महामारी से पीड़ित होने का डर युवाओं और उन युवाओं पर आश्रित दोनों ही लोगों पर भारी पड़ रहे हैं।इन सब प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी नौकरी जाने के डर के साथ ही एक सुकून भी है कि अब उन्हें रोज के संक्रमण के डर से मुक्ति मिल गई है।कुल मिलाकर लेख के माध्यम से यह सार निकलता है कि बेरोजगारी का दर्द कोई नया नहीं है किन्तु इस महामारी काल में जो युवाओं के सपने और कुछ उनके अपने दोनो का ही विछोह हुआ है संभवतः ये मनोवैज्ञानिक दंश जाते जाते ही जाएगा और इस दंश के निशान फिर भी शेष रह जाएंगे।

चीन का काल राइफल मैन जसवंत सिंह

जसवंत सिंह रावतपौडी गढवाल जिले के रहने वाले थे जो उत्तराखंड राज्य में आता है।जसवंत सिंह दूसरी कोशिश में सेना की चौथी बटालियन में वो राइफलमैन के पद पर भर्ती हुए उस समय उनकी आयु मात्र 17 वर्ष थी।1962 को चीन और भारत के युद्व में जशवंत सिंह रावत शहीद हुये थे। ऐ शहीद हुये थे19 नवम्बर 1962 में जषवंत सिंह रावत ने युद्व में चीन के 1000 सैनिकों को अकेले ही 72 घंटे तक रोका रखा उन्होंने अरूणांचल प्रदेश की मोन पाजन जाति की दो लडकियों नूरा और सेला की मदद से फायरिंग ग्राउंड बनाया वो उन दो लडकियों के सहयोग से तीनों जगह पर बार बार जाकर हमला करते रहे जिससे दुश्मन को पता न चले कि वो अकेले है अंत में उन्हें जो राशन मुहिया कराता था,उसे चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया और उसने मौत के डर से जसवंत सिंह की पूरी हकीकतबतादी। फिर चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह को चारो तरफसे घेर लिया और इस लडाई में सेला वीर गति को प्राप्त हुई तथा नूरा को चीनी सैनिकों ने पकड लिया इन्होंने चीन के सैनिको के हाथ लगने से अच्छा फॉसी पर झूलना ठीक समझा और बाबा जषवंत सिंह फॉसी के झूला पर झूल गये। आज वो शहीद होने बाद भी भारत की सीमा की रक्षा कर रहेहै। जषवंत सिंह को जहां वो शहीद हुये थे,

वहां पर एक मंदिर बना है और उनको बाबा के नाम से पुकारा जाता है। जषवंत सिंह के इस मंदिर की खाशियत यह है कि मंदिर में उनका एक कमरा भी बना है,जिसमें बाबा आराम करते हैं और सुबह वो डयूटी पर चले जाते हैं। यह सुनकर आपको विश्वास तो नहीं होगा पर यह हकीकत है। उस मंदिर की देख रेख करनेवालेजवान ने बताया कि जब सुबह उनके जूतों को पालिस करके रखा जाता है तो शाम के समय उनमें मिटटी लगी हुयी मिलती है सुबह उनके बिस्तर भी अस्त व्यस्त मिलते है वहां पर तैनात सैनिकों अनेक बार बाबा उनके सपनों में आये है,और वो सपने में यह भी कहते हैं कि-तुम को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मैं तुमको 72 घंटे पहले ही सूचित कर दूँगा कि चीन के सैनिक कहॉ पर हैं।

भारत सरकार ने इनको देवता की उपाधि दी है। जब ये शहीद हुये थे। तब इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था जब चीन के सैनिकों ने हमला किया था तब ये अकेले थे इनके नाम के आगे कभी भी स्वर्गीय नहीं लगाया जाता है इन्हें आज भी छुट्टियां मिलती हैं और प्रमोशेन तथा पोस्ट भी मिलती है जशवंत सिंह की बहादुरी चीन भी सलाम करता है। चीन आज भी उस रास्तेसेगुजरतेवक्त इनके आगे सर झुकाकर जाता है।

पुरुलिया पुलिस का दम अपराधी हुए बेदम

ब्यूरो चीफ अमन राय

कहते हैं पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं अपराधी चाहे लाख शातिर क्यों न हो एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़े ही जाते हैं इस बात को सच साबित किया है पुरुलिया जिला की पुलिस ना केवल लोगो की सुरक्षा के लिए तत्पर है बल्कि सामाजिक दायित्व को भी बखूबी निभा रही है चाहे ट्रैफिक की बात हो या रक्तदान या फिर पौधारोपण पुलिस ने हर जगह अपनी सक्रियता से लोगों में एक अनूठी छाप छोड़ी है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दरमियान भी पुलिस ने लोगों को हर संभव सहायता कर मानवता का एक परिचय दिया है वहीं दूसरी और बात करें तो जब भी जिले में अपराधियों ने अपराध करने का प्रयास किया है तब तब् उन्हें मुंह की खानी पड़ी है ताजा मामला सामने आया है एक ऐसे गिरोह का जो खाली घरो को अपना निशाना बनाते थे मामला है पुरुलिया के रघुनाथपुर थाने की. इलाके में कुछ दिनों से कुछ अपराधी पूरी सक्रियता के संग पहले खाली घरों को अपना निशाना बनाते और लूट कर सोने गहने ले चंपत हो जा रहे थे. पहले गैंग के शातिर इलाके का मुआयना करते किसी फेरीवाला बनकर कुछ बेचने के बहाने या बंदर वाला का खेल दिखाने के बहाने इलाके में घुस जाते थे फिर जब इन्हें यह पूरी तरह निश्चित हो जाते कि यह घर खाली है और इसके मालिक का अभी आना संभव नहीं है तो उस घर को अपना हाथ साफ कर देते. एक के बाद एक घटी इस घटना से पुलिस पूरी तरह परेशान थी फिर रघुनाथपुर थाने के इंस्पेक्टर आफ पुलिस एस.चट्टाराज ने एक टीम बनाई और इलाके में नजर रखने को कहा देखते ही देखते इस टीम को एक मुखबिर के माध्यम से यह खबर पुलिस को मिल गई कि शातिर अपराधी एक घर जो स्थानीय विवेकानंद पल्ली के एक घर को निशाना बनाने वाले हैं पुलिस ने पूरी सक्रियता के संग इस टीम को धर दबोचा विजय केवड़ा, संजीव एवं रहीम सिंह को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा पहले तो यह लोग पुलिस को बरगला रहे थे लेकिन फिर यह टूट गए और पुलिस को सारी सच्चाई उगल दी. इसके साथ ही जिस सुनार के पास यह लूट का सामान सोने गहने बेचते थे उस दुकानदार को भी पुलिस ने पकड़ा है रघुनाथपुर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखी जा रही है इलाके के लोगों में पुलिस प्रति विश्वास बड़ा है.

इनका कहना है: हमने इस चोरी कांड से जुड़े आरोपियों को पकड़ा है. अब इनसे इस बात की पूछताछ की जाएगी कि इनके गैंग में और कितने लोग हैं मामले की जांच चल रही है.

एस सिल्वा मुर्गन एसपी पुरुलिया

रिश्तों का मोल

एक गाँव मे दो भाई रहते थे। राजू और रामू दोनों बहुत ही पक्के व सच्चे मित्र थे । दोनों भाई साथ साथ सब काम करते । गाँव वाले बोलते थे इन दोनों भाई हमेशा साथ ही रहते हैं। दोनों साथ में स्कूल जाते । खेलने कूदने जाते। और दोनों एक साथ बड़े भी हुये। दोनों की उम्र काम करने की हो गयी। दोनों सच्चे व ईमानदार आदमी थे। दोनों शहर जा कर काम ढूंढ लिये । रामू और राजू को एक कंपनी में काम मिला ।इस बात का दोनों के माता - पिता को बहुत खुशी हुई कि आज के युग मे दोनों भाई में कितना प्रेम है। अब भी दोनों साथ रहते थे और काम मे जाते थे। दोनों की शादी भी हो गयी । राजू और रामू एक ही जगह घर बनाकर रहने लगे। राजू ओवर टाइम करता था इसलिये उसके पास ज्यादा पैसे आने लगे । और रामू एक ही बार काम करता था तो सिर्फ तनख्वा के ही रुपय मिलते थे। धीरे धीरे राजू को पैसे का घमंड होने लगा । कि मेरे पास ज्यादा पैसे है मैं बहुत ही अमीर आदमी बन गया हूँ। रामू को इस बात का पता चला तो राजू को बहुत समझाया कि देखो भाई पैसे का घमंड करना छोड़ दो। और सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को अच्छे से निभाओ पैसा हमेशा काम नही आता ।रिश्तेदार ही काम आते हैं। राजू रामू से बहस करना शुरू कर दिया। बोला आजकल पैसा ही सब कुछ हैं रामू तू क्या समझेगा तू तो आज भी गरीब है और देख मेरे को मै कितना अमीर इंसान बन गया हूं। राजू , रामू और सभी रिश्तेदारों से दूर हो गया । एक दिन अचानक राजू का तबियत बिगड़ने लगा। उसको केंसर हो गया था। इलाज में सभी पैसे खत्म हो चुके थे। तभी अचानक राजू को रामू की याद आई।और अपनी पत्नी से कहा रामू को फोन लगाओ।उसकी पत्नी रामू को फोन लगाकर सब कुछ बताई।रामू तुरन्त वहाँ हॉस्पिटल में आया। और राजू की हालत देख कर दोनों गले मिलकर रोने लगे। तब राजू को समझ आ गया कि दोस्ती और रिश्तों का मोल क्या होता है। रामू , राजू को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जा कर इलाज कराया और राजू की जान बचाया। तभी राजू , रामू के पैरों में गिर कर माफी माँगने लगा और कहने लगा कि जब तू समझाया उसी समय मैं समझ जाता तो अभी मेरी ये हालत नही होती मैं पैसे के मोह में पागल हो गया था। अब मेरे पास सिर्फ तू ही हैं रामू ऐसा कहकर दोनों रोने लगे। तभी रामू ने कहा ऐसा मत बोल भाई समय रहते तुझे गलती का एहसास हो गया और क्या चाहिये। फिर दोनों भाई पहले जैसे ही साथ साथ रहने लगे।

प्रिया देवांगन प्रियू
पंडरिया
जिला -कबीरधाम

नवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं

जय श्रीराम बघेल
जिला अध्यक्ष
जिला कांग्रेस कमेटी भिण्ड(म.प्र.)

गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता

अली खान
(स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार)
जैसलमेर, राजस्थान

अहिंसा के प्रबल समर्थक, शांति के अग्रदूत? और? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। मौजूदा वक्त में बढ़ती भूखमरी, बेरोजगारी, विश्व हिंसा, वैश्विक आर्थिक मंदी और आपसी वैमनस्यता के बीच गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। दुनिया में समरसता, सद्भाव, अहिंसा और सत्य की बात करने वाले गांधी जी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने अपने विचारों से न केवल भारतीयों को प्रभावित किया बल्कि समूचे विश्व को प्रेरित भी किया। एक समय विदेशी महात्मा गांधी जी को अकसर संबोधन में अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया करते थे। गांधी को संबोधन में अर्धनग्न फकीर कहा करते थे। यद्यपि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में अनेक कष्ट और यातनाएं झेली। गांधी जी को एक बार नस्लभेद के आधार पर ट्रेन में सफर करने से वंचित कर दिया था। यह वाकया गांधी जी के साथ अफ्रीका में हुआ। जब उनके पास प्रथम श्रेणी की वैध टिकट होने के बावजूद उन्हें तीसरी श्रेणी के डिब्बे

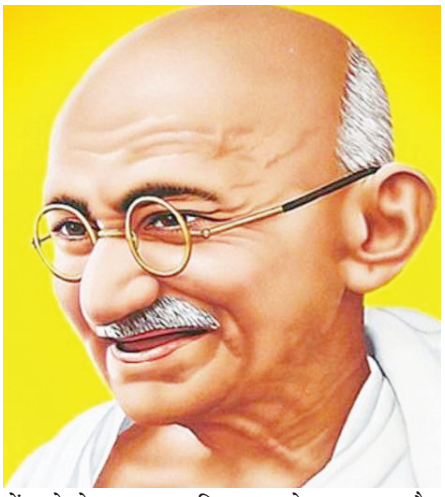

में जाने से इनकार कर दिया, जब वे पायदान पर बैठ गए तो एक यूरोपियन को कुछ नागवार गुजरा उसने गांधी जी को धक्का देकर ट्रेन में सफर से वंचित कर दिया था। इस वाकये पर एक बार गांधी जी से किसी ने सवाल किया, तब गांधी जी ने जवाब दिया कि आंख के बदले? आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। उन्होंने आगे कहा कि मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण हैं, किंतु मेरे पास किसी को मारने का कोई भी कारण नहीं है। महात्मा गांधी जी ने अपना तन, मन और धन राष्ट्र के हित में समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी जी ने 200 वर्षों की दीर्घकालीन पराधीनता के पश्चात भारत को स्वाधीनता के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया।? गांधी जी ने नस्लभेद मिटाने के साथ-साथ हरिजन हितार्थ और हिन्दू-मुस्लिम में एकता स्थापित करने के कई प्रयास भी किए। गांधी जी ने चंपारण से स्वाधीनता की बिगुल बजाई और खिलाफत में हिंदू-मुस्लिम की एकता की अद्भुत मिसाल पेश की। उनकी अगुवाई में उद्-घोष करो या मरो ने देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई। गांधी जी ने शिक्षा के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। वह सिद्धांत बुनियादी शिक्षा को लेकर था। गांधी जी का बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उस समय था। गांधी जी अपने बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों में बच्चे का सर्वांगीण विकास, अच्छे चरित्र का निर्माण, आदर्श नागरिक बनाने के साथ-साथ उसे स्वावलंबी बनाने की बात करते थे। यद्यपि हम भारतीय गांधी जी के स्वाधीनता संग्राम में योगदान को को कभी नकार नहीं सकते। लेकिन आज देश में गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गांधी जी के विचारों को ताक पर रखकर कई अनुचित प्रकृति के कदम उठाए जा रहे हैं। जो वाकई बेहद चिंताजनक है। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के बारे में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने बिलकुल सटीक कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़-मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था।

नारी

जीवन की जननी है कुदरत का अभिमान है
कहलाए नारी वो ईश्वर भी करता उसका सम्मान है,
मां बनकर तुम्हें बुरी नज़रों से बचाती
कोई भी दुख तुम्हारा देख नहीं पाती
तुम्हारे में ही बस्ती हरदम उसकी जान है,
बहन बनकर मांगती तुम्हारे लिए दुआएं
सुनती तुम्हें और अपने सर लेती तुम्हारी बलाएं
सह नहीं पाती तुम्हारा जो अपमान है,
पत्नी बनकर सुख दुख सारे साथ निभाती
प्रेम देकर तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाती
कठिन जीवन को बनाती आसान है,
बेटी बनकर देती तुम्हारे नाम को आधार
घर की रौनक बनती ना करती तुम्हें लाचार
कन्यादान का पुन्य दिलाती करती तुम्हें महान है,
सबके घर बसने वाला एक सा वरदान है
सम्मान करो! दो इनको जो इनका स्थान है।

कवि स्वामी दास, कवि लेखक

सपना आधी रात का

गीली बोझिल पलकें मुस्कुरा रही है वो करीब आकर कह रहे है
रहने दो पल्लू को लहराता मत ड़ालो कमर के घोंसले में पसीना पिता सिकुड़ जाएगा,
लगता है जैसे शहर के हर रास्ते समा गए हो दौड़ कर आकर तुम्हारी कमर के आसपास. !
वो हस्त मिलाप की मखमली छुअन आज छोटे गाँव की पगदंडीयों सी खुरदुरी लग रही है, हाथ में हाथ दो चुम्बन की मोहर से महका दूँ , कहो कैसा लगा?

(भावना ठाकर
बेंगलोर) भावु

थकान से निढ़ाल अर्धध्वस्त सी तुम बस मेरे पहलू में बैठकर मेरी बेतहाशा चाहत में ढूँढो सुकून के पल,
बिखरे जुड़े में बेमिसाल लगती हो,
आओ तुम्हारे बिखरे जुड़े से चुनकर जिम्मेदारीयों के कण पिरो लूँ मैं अपनी हथेलियों की लकीरों में. !
पूरे घर के कोने-कोने से आकर जो बस गई है तुम्हारे रोम-रोम में, मरी, मसाले फ़िनाइल, साबुन की ये जो आती है खुशबू तुम्हारे बदन से हमारे असबाब की, नासिका को बहका रही है,
मैं ऋणी हूँ तुम्हारा
तुमने अपने पसीने से जो सिंचा है मेरे घर की नींव को. !
आओ आज सोख लूँ तुम्हारे तन से वो पसीना तुम्हारी पीठ से चुनकर जिम्मेदारीयों के ज़ख्मो को गले लगा लूँ,
मरहम लगाने दो मेरे लबों की खुशबू से, तुम ठंडी फूँक की सरसराहट में बह जाओ,
पलकें मूँदे करवटों को भूलकर मेरे सीने पर सर रखकर सो जाओ. !
आधी रात को ये खुशी के आँसू से सजा गिलाफ़ हंसता क्यूँ है ?
ओह काश की ये सपना सुबह का होता सुना है सुबह के सपने सच होते है.. !!!
दूर दूर बिस्तर के उस छोर से बेफ़िक्री के खर्राटों के शोर में दब गए है एहसास मेरे
गीली बोझिल पलकें मुस्कुरा रही है।।

निर्धन अन्नदाता

ये निर्धन कृषक जो कहलाता तो है अन्नदाता,
पर किसने पूछा क्या दो जून रोटी भी है पाता।
बाढ़ आती, सारी फसलें मवेशी बहा ले जाती,
किसान बेचारा असहाय हो ताकता ही रह जाता।
सूखा जो पड़ जाए तो बीज तक भी जल जाए,
हल लिए साथ निर्निमेष दृष्टि से आँसू बहा जाता।
अच्छी हो जाए उपज तो आकर कम्बख़्त दलाल,
औने पौने दामों में फसल का सौदा सब कर जाता।
वह हाड़ तोड़ मेहनत करने से किंचित न घबराता,
देख जलद को गगन में आशा का दीप जलाता।
बेटी की शादी बेटे की शिक्षा उसके मात्र स्वप्न हैं,
निराई गुड़ाई हो चुकी वर्षा पर उम्मीद टिकाता।
सिंचाई का साधन नहीं प्रकृति ने भी छोड़ा साथ,
उकडूं बैठा ये सोचकर दिल तक उसका घबराता।
पेट पीठ हो गए एक हैं अब भूखे रह रह कर,
साहूकार का कर्ज़ सुरसा के मुँह सा बढ़ता जाता।
अंतिम आशा की किरण से जो ये बादल न बरसे,
कहीं जोड़ना न पड़ जाए फाँसी से मुझ को नाता।

नीलोफ़र नीलू वरिष्ठ कवयित्री
देहरादून-उतराखण्ड

न जाने क्यों

न जाने क्यों
खो सा गया है कही
मेरा मन।

.....

न जाने क्यों
मिट्टी सा हो गया है
मेरा तन।

.....

न जाने क्यों
टूट गया है,
उनकी याद में
हृदय का हर एक कण।

.....

न जाने क्यों
बिखर गए है,
हर ख्वाब मेरे
फिक्र में उनकी हरदम।

राजीव डोगरा विमल
कांगड़ा हिमाचल प्रदेश (युवा कवि लेखक)
(भाषा अध्यापक)

पिता

घर का मज़बूत स्तंभ होते हैं ।
प्रेम, स्नेह की छांव रखते हैं ।
जिनके बिना सब ख्वाब अधूरे ,
वो तो बस पिता ही होते हैं ।

दुख अपना जो न दिखलाते ।
कड़ी धूप मशक्कत करते ।
भरकर झोली खुशियों से ,
सदैव परिवार को वह बांधें रखते ।

स्पर्श की अपने थपकी देते ।
सर पर प्यार से हाथ हैं धरते।
चाहे कोई भी विपदा आ जाए ,
हौंसला देकर सदैव आगे बढ़ाते ।

जीवन जीने की राह दिखाते ।
विफलताओं से लड़ना सिखाते ।
कभी ड़ाटकर ,कभी प्रेम से ,
सत्यता का वो पाठ पढ़ाते ।

असफलताओं से कभी न थमते ।
निरंतर आगे बढ़ते जाते ।
घर की मज़बूत चट्टान हैं वो,
पिता के चरणों में सारे धाम समाते ।

रश्मि वत्स
मेरठ(उत्तर प्रदेश)

संघर्ष बहुत कुछ सिखाता है

इंसान जब जन्म लेता है तब से उसकी जिंदगी का सफर प्रारंभ हो जाता है।

बहुत सारी छोटी-बड़ी गलतियों से, ठोकरों से वह गुजरकर आगे बढ़ता है।

बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोता भी है।

बहुत सारी सुंदर कल्पनाओं को, बहुत सारे सुंदर सपनों को अपनी आंखों में सजायें बस चलता रहता है, कभी पैरों में घाव हो जाते हैं तो कभी हिम्मत जवाब दे जाती है।

कभी खुद को, कभी किस्मत को कोसकर मन का गुबार निकाल देता है,पर सफर फिर भी तय करना होता है।

इस सफर में उसका सच्चा साथी उसका संघर्ष होता है,जो उसे भेंट में अच्छें-बुरें अनुभव देता है,जिनकी मदद से वह आगे के रास्ते के लिए सजग और अगले कदम के लिए तैयार हो जाता हैं।

ये संघर्ष ही होता है जो कभी जीत पर घमंड नहीं करने देता,वह हमेशा बताता है कि इंसान का रिश्ता जमीन से कितना गहरा है,ये संघर्ष के दिन ही होते हैं जो धूप-छांव का महत्व बताते हैं और जीवन को सार्थक करते हैं।

अंकिता जैन अवनी
(लेखिका/ कवयित्री) अशोकनगर

मां दुर्गा का आगमन प्रशासन तैयार

ब्यूरो चीफ अमन राय

दुर्गा पूजा देश ही नहीं विदेशों में भी भारतीय मूल के निवासी मनाते हैं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा विश्व प्रसिद्ध है यहां दुर्गा पूजा को लेकर महीनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है मूर्तियां हो या पंडाल बनाने वाले कारीगर काफी उत्साह के संग इसे बनाते हैं यहां की बनाई हुई मूर्तियां विदेशों तक जाती है लेकिन इस बार के पूजा में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रशासन ने एक गाइडलाइन जारी की है हर पूजा कमेटियों को सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की जाएगी साथ ही दर्शनार्थी भी निर्देशों के अनुसार पंडाल एवं प्रतिमा दर्शन करेंगे. सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों पर कार्रवाई भी हो सकती है. दिशा निर्देशों में यह कहा गया है पंडाल को चारों तरफ से खुला रखना अनिवार्य होगा प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर अनिवार्य है सभी को मार्क्स पहना अनिवार्य होगा अगर किसी ने मास्क नहीं पहना है तो आयोजकों द्वारा मास्क उपलब्ध कराई जाएगी. सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा दर्शन करेंगे लोग. आयोजकों को इस बार वोलेंटियर की संख्या बढ़ानी होगी. सांस्कृतिक अनुष्ठान नियमों को ध्यान में रखते हुए करने की बात कही. पश्चिम बंगाल सरकार लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में वर्चुअल मीटिंग के द्वारा राज्य के सभी जिले के प्रशासनिक अधिकारी एवं आयोजकों को संबोधित किए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कोरोना महामारी की वजह से आयोजकों को इस बार पूजा की तैयारी में दिक्कतें आएंगी इस को ध्यान में रखते हुए सभी कमेटियों को ?50000 की सहायता राशि दी जाएगी साथ ही बिजली बिल में भी 50त्न की छूट दी जाएगी इसके अलावा दमकल सहित कई अन्य परीसेवाएं देने की घोषणा की गई. पश्चिम बंगाल में कुल 37000 पूजा कॉमेटीया है इससे आयोजकों में तो खुशी देखी गई. लेकिन दूसरी ओर देखें तो दुर्गा पूजा को लेकर छोटे बड़े व्यवसाई सभी असमंजस की स्थिति में है व्यवसाई बताते हैं कुछ लोग मार्केट में आ तो रहे हैं लेकिन खरीदारी उस तरह नहीं हो पा रही है सभी व्यवसाई इसका कारण कोरोनावायरस का प्रभाव बता रहे हैं कुछ कपड़े के व्यवसाई ने तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ ही दी है और कुछ अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं. दुर्गा पूजा को लेकर हमारे संवाददाता अमन राय ने जिले का जायजा लिया जिसमें जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों एवं आयोजकों से बात की सभी का एक ही लक्ष्य था शांतिपूर्ण ढंग से दुर्गा पूजा संपन्न हो.

इनका कहना है

प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं सक्रिय है. त्योहारों को मनाए साथ ही सतर्क रहें. मास्क पहने हैंड सेनीटाइजर का इस्तेमाल करें. किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं. प्रशासन का सहयोग करें. दुर्गापूजा दशहरा सहित सभी त्योहारों के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

मलाई घटक. मंत्री. पश्चिम बंगाल सरकार

किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा. दिशानिर्देशों का पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी होगी. हमें उम्मीद है सभी इसका ख्याल रखेंगे और पूजा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न होगी.

अभिषेक गुप्ता डीसीपी

आयोजकों के संग बैठक की गई है. गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन करने को कहा गया है. ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रखना हमारी जिम्मेदारी होगी. प्रशासन का सहयोग करें सभी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे.

अनामित्रा दास. डीसीपी वेस्ट

प्रशासन के नियमों को मानते हुए हम लोग दुर्गा पूजा की पूरी तैयारी किए हुए हैं. मास्क हैंड सेनीटाइजर आदि की व्यवस्था हम लोगों ने की है. प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है. मुझे उम्मीद है पूजा के दौरान किसी भी दर्शनार्थी को परेशानी नहीं होगी.

कवि दत्ता. आयोजक

सरकारी विभागों के अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए जल्द ही कोई पॉलिसी बनाई जाए

रघुबीर ठाकुर

रियासी में भाजपा नेता जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कार्यकारी सदस्य श्री पवन देव सिंह एडवोकेट ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा से आग्रह किया कि जम्मू कश्मीर में भिन्न भिन्न सरकारी विभागों के अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने के लिए जल्द ही कोई पॉलिसी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अस्थाई ही सेवानिवृत हो गए हैं और कुछ होने की कगार पर है। जबकि अस्थाई कर्मचारियों के सहयोग से ही कुछ विभाग चलते है जिसका उदाहरण देते हुए उन्होंने जल शक्ति विभाग जो कि पहले पी. एच. ई विभाग के नाम से जाना जाता था । उस विभाग में वर्ष 1994 के बाद ऑपरेशनल स्टाफ की भर्ती आजतक नहीं हुई है, जबकि अरबों रुपए की नई स्कीमें उसके बाद लागू की गई हैं और यही डेली वेजर स्टाफ उनको चलाता आया है। लेकिन उनको ना तो समय पर वेतन मिलता है और जो वेतन मिलता भी है वह मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत नहीं मिलता है। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिसके कारण उनको अपने परिवार के पालन पोषण में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि रियासी में चाहे

कटरा वैष्णो देवी जो के बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटक स्थल है वहां भी 80 प्रतिशत से भी ज्यादा अस्थाई कर्मचारियों की वजह से ही पेयजल आपूर्ति की जा रही है और पूरे जम्मू कश्मीर में भी जितनी बड़ी बड़ी पेयजल की प्रोजेक्ट्स हैं उनको अस्थाई कर्मचारी ही चलाते हैं। विभिन्न विभागों में भी ऐसी ही स्थिति है चाहे वो विद्युत विभाग हो या कोई और विभाग हो, उन्होंने एल जी साहब से पुरजोर अपील की है कि जितने भी अस्थाई कर्मचारी हैं उनको नियमित करने के लिए जल्द से जल्द नीति बनाई जाए ताकि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वह बंद हो सके और मिनिमम वेजेस एक्ट की वॉयलेशन जम्मू कश्मीर में बंद हो सके। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया के कुछ अस्थाई कर्मचारियों से जल शक्ति विभाग ने यह कहकर की उनको स्थाई किया जाएगा उनकी हजारों कनाल जमीनें विभाग के नाम डोनेट करवाई लेकिन आजतक उनको भी स्थाई नहीं किया गया इस बारे में भी जांच की जाय और उनको स्थाई किया जाए। और अंत में उन्होंने यह भी अपील की के जल जीवन मिशन का कार्य जम्मू कश्मीर में जल्द पूरा किया जाय । वार्ता के दौरान विजय रस्याल (जम्मू कश्मीर यू. टी) भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य और हिम्मत सिंह भाजपा नेता भी मौजूद रहे।

देश में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर सांबा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया

अमित कुमार ब्यूरो चीफ

सांबा। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू-कश्मीर इकाई के नेताओं ने देश में बलात्कार की बढ़ती धटनाओ पर आज सांबा में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया । पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मनीश साहनी के नेतृत्व में दर्जनों शिव सैनिकों ने यूपी के हाथरस एवं बलरामपुर में गैंगरेप एवं पीड़िता के दाह संस्कार को लेकर यूपी पुलिस द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। साहनी ने कहा कि देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी राष्ट्र की बेटियों में असुरक्षा का माहौल है। साहनी ने रेप एवं गैंगरेप जैसे घिनौना अपराध करने वालों को बीच चौराहे फांसी दी जाने की मांग की गई । उन्होंने कहा कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी की वारदातें हर साल बढ़ती जा रही हैं। कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चिरमिरा गई है और मुख्यमंत्री योगी जी पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। वहीं मीडिया को पीड़िता के दाह-संस्कार कवर करने पर रोके जाने की कड़ी आलोचना करते हुए, साहनी ने कहा कि यूपी प्रशासन की मीडिया के साथ गुंडागर्दी , मीडिया की आज़ादी पर हमला है । वहीं पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष मीनाक्षी ने कहा कि वर्ष 2019 मे महिलाओं के साथ अश्लीलता की 300

से अधिक घटनाएं घटी है । एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा मिनाक्षी ने कहा कि यूपी में प्रतिदिन 11 बलात्कार के मामले सामने आते हैं और 20 प्रतिशत से भी कम आरोपियों को सजा मिल पाती है इस अवसर पर महासचिव विकास बख्शी, कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी गुप्ता, सचिव राज सिंह रमेश गुप्ता, विजय मनवाल , राजू सलारिया समेत कई अन्य नेता मौजूद थे।

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वास्तविक सर्वे की जाए

गरीबों की योजना का लाभ अमीरों के परिवार को मिल रहा

नेनाराम सिरवी, पाली (राजस्थान)

कोराना जैसे भीषण संकट काल की स्थिति के दौरान गरीब वर्ग की योजना का लाभ अमीर वर्ग के परिवार को मिल रहा .पाली पंचायत समिति एवं रानी पंचायत समिति के कई ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीब से गरीब एवं मजदूर वर्ग का परिवार मुख्य सहायता योजना से वंचित. ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित एवं गरीब वर्ग का परिवार मुख्य योजना से वंचित रहने का मुख्य कारण वास्तविक सर्वे नहीं हुई. पक्षपात एवं निजी स्वार्थ को लेकर गलत सर्वे के अनुसार गरीब वर्ग का परिवार काफी लंबे समय से इस योजना में जुड़ा हुआ . पक्षपात के कारण अशिक्षित एवं गरीब से गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रखा.जिले के कई ग्राम पंचायत स्तर पर लगभग हर ग्राम पंचायत के सहायक एवं राजस्व गांव की जनता खाद्य सुरक्षा योजना से कई परिवार आज भी वंचित लेकिन . अशिक्षित एवं गरीब परिवार की आवाज ग्राम पंचायत मुख्यालय से बाहर तक सीमित रहती . अमीर परिवार की आवाज अपने मुख्य आवास से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सीधी पहुंच जाती हैं जिससे अमीर परिवार गरीबों की मुख्य योजना में जुड़ कर गरीब बन जाता है.विश्वव्यापी महामारी के चलते संपूर्ण देश में एक साथ लगाया गया लॉक डाउन की मार अमीर परिवार के साथ गरीब परिवार भी झेल रहा. लेकिन सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन सामग्री गरीब परिवार को नहीं मिल रही और अमीर परिवार को मिल रही हैं.ऐसे कई परिवार जो इस योजना से काफी लंबे समय से जुड़े हुए लेकिन बीते समय में की गई सर्वे के अनुसार गरीब परिवार का खाद्य सुरक्षा योजना से कट गया. कोराना वायरस की भयंकर विश्वव्यापी महामारी के चलते गरीब वर्ग का परिवार रोजगार की आई कमी के कारण भारी परेशान नजर आ रहा है. ऐसी विपरीत संकटकाल की स्थिति के दौरान ऐसे परिवार को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए. लेकिन अमीर परिवार को खाद्यान्न सुरक्षा सामग्री योजना

के तहत निशुल्क सामग्री गेहूं मिल रहे हैं. कई ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के योजना का लाभ अमीरों को मिल रहा और अमीर परिवार निशुल्क मिली हुई राशन सामग्री गेहूं वापस गरीब परिवार को बेच देते हैं. कोराना संकट काल के दौरान निशुल्क गेहूं मिले और इससे पहले दो रुपए किलो मिलते थे. दो रुपए किलो गेहूं गरीब परिवार को 12 रुपए से अधिक किलोग्राम के अनुसार बेच रहे. गरीब परिवार के पास रहने के लिए पर्याप्त रूप से सुविधा नहीं होने से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ नहीं मिल रहा. अमीरों के पास पर्याप्त रूप से सभी सुविधा होने के कारण खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन सामग्री मिल रही .इस दौरान इस मुख्य योजना के तहत गरीब वर्ग का परिवार लगभग हर ग्राम पंचायत स्तर पर वंचित . गरीब जनता द्वारा बताया गया कि वास्तविक सर्वे करके खाद्य सुरक्षा सामग्री योजना के तहत गरीब वर्ग के परिवार को जोड़ा जाए. प्रतिमाह राशन सामग्री मिल रही है लेकिन राशन सामग्री स्थल पर लंबी लंबी लाइन की कतारों में गरीबों की संख्या कम और अमीरों की संख्या ज्यादा. ग्रामीण क्षेत्रों में पक्षपात जातिवाद के कारण खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कभी गरीब वर्ग का परिवार इस योजना से वंचित हैं. इस दौरान वास्तविक सर्वे जिले में वापस की जाए और अशिक्षित एवं गरीब से गरीब वर्ग के परिवार को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाए. लगभग 4 वर्षों पहले नए राशन कार्ड बनाए गए थे जिसमें अभी तक बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जिनके राशन कार्ड के सभी पृष्ठ मैं सरकार द्वारा दी जाने वाली योजना का के तहत सामग्री के बारे में किसी भी प्रकार का नामकरण नहीं पूरी तरह से राशन कार्ड खाली अवस्था में पड़े हुए हैं. इस दौरान गरीब वर्ग की जनता द्वारा बताया गया कि राशन कार्ड का लाभ किस योजना के तहत मिलेगा और कब मिलेगा. नए राशन कार्ड बनवाने के लिए शिक्षित एवं गरीब वर्ग के परिवार को दस्तावेज अपलोड कराने के लिए कई बार छोटे बड़े संबंधित विभागीय कार्यालय में चकर कांटे और नए राशन कार्ड बनाए गए. लेकिन नए बनाए गए राशन कार्ड के माध्यम से किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला. इस दौरान गरीब वर्ग के परिवार द्वारा सरकार के प्रति भारी रोष जताया और बताया गया कि एक बार जिले में वास्तविक सर्वे की जाए और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अशिक्षित गरीब से गरीब वर्ग के परिवार को योजना के तहत जोड़ा जाए जिससे आम परिवार को राहत मिले।

ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजना के कार्यों की शुरुआत

नेनाराम सिरवी, पाली (राजस्थान)

राजस्थान पंचायत राज विभाग के अंतर्गत ग्रामीण सरकार ग्राम पंचायत द्वारा विकास की योजना के कार्य की शुरुआत की गई. जनवरी 2020 ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार के चुनाव संपन्न हुए. कोराना वायरस के खतरनाक फैलाव के कारण ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजना के कार्यों की शुरुआत अगस्त माह से शुरू किए गए. पाली पंचायत समिति एवं रानी पंचायत समिति के कई ग्राम पंचायत द्वारा स्वस्थ भारत अभियान ग्रेवल सडक जलभराव की समस्या सीसी रोड उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुलभ शौचालय आदि सहित अनेक विकास के योजना के कार्य हर ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू किए गए. पाली पंचायत समिति ग्राम पंचायत सोडावास सरपंच राधा देवी सिरवी वडेर वास सरपंच लीला देवी सिरवी खेरवा सरपंच संतोष कंवर रुपावास सरपंच सुरेश बंजारा मनिहारी सरपंच भैरों सिंह शेखावत डरी सरपंच जब्बरसिंह जोधा. भांगेसर सरपंच हबीब खान. हेमावास सरपंच मोहनलाल पटेल.टेवाली सरपंच जोगा राम कुमावत.बोमाडडा सरपंच जोगाराम सरगरा. लांबिया सरपंच मदन लाल मेघवाल.बाणियावास सरपंच सीता.डेडा सरपंच दिलीप सिंह सोनीगरा.गिराडरा सरपंच मंगला राम मीणा गुड़ा एंडला

सरपंच मीनाक्षी मीणा. रानी पंचायत समिति ग्राम पंचायत.चाचोडी. सरपंच पूनम सिंह राजपुरोहित मांडल सरपंच सुराराम माली .बालराई सरपंच केसाराम कुमावत. खोड सरपंच दुर्गेश दाधीच. कीरवा सरपंच घिसी देवी सिरवी.रोहिट पंचायत समिति ग्राम पंचायत निमली उड़ा सरपंच मोना शर्मा. सोजत पंचायत समिति ग्राम पंचायत सुरायता सरपंच प्रेम सीरवी बिलावास सरपंच डिंपल सीरवी मंडला सरपंच दलपत सीरवी मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति ग्राम पंचायत हिंगोला सरपंच गोविंद राम मेघवाल. आदि सहित लगभग सभी ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्थान पंचायत राज विभाग के तहत विकास की योजना के कार्यों की शुरुआत की गई. सोजत पंचायत समिति ग्राम पंचायत बिलावास सरपंच डिंपल सीरवी के नेतृत्व में 1501 वृक्ष लगाए गए वडेर वास सरपंच लीला देवी सीरवी के नेतृत्व में प्रभु प्रेमी गौशाला एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय सार्वजनिक जगहों पर वृक्षारोपण किया गया. सोडावास सरपंच राधा देवी सिरवी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया.खेरवा सरपंच संतोष कंवर के नेतृत्व में तालाब एवं सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण किया गया. रानी पंचायत समिति निवर्तमान प्रधान नवरत्न सिरवी एवं ग्राम पंचायत.सिवास. सरपंच फूसाराम सिरवी ग्राम पंचायत.ढारिया. सरपंच रुकमा देवी सीरवी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया. ग्रामीणों को सरकार की हर योजना की मदद देने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा संपूर्ण प्रयास किए जाएंगे. खेरवा सरपंच संतोष कवर वडेर वास सरपंच संपूर्ण ग्राम पंचायत सरपंच एवं सरपंच प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की अशिक्षित जनता एवं गरीब से गरीब वर्ग के परिवार को सरकार की हर योजना की जानकारी और सरकार की हर योजना का लाभ दिलाने के लिए संपूर्ण प्रयास ग्राम पंचायत द्वारा किए जाएंगे.

पिडिंत व्यापारियों से मिले स्वामी तेजानंद महाराज

नारायणलाल सैणचा

चैन्नई। तमिलनाडु पौन ब्रोकर्स एंवम् ज्वैलर्स एसोशिएसन संगठन के माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय स्वामी तेजानंद महाराज ने बुधवार को तिरुवनामलैइ, रानीपेट और वैलूर जिले के कई व्यापारियों और क्षैत्रीय पदाधिकारियों से शिष्टाचार भेंट करके क्षैत्र के व्यापारियों की समस्याओं,व्यापार में आ रही परेशानियों और उनके निवारण पर चर्चा की। इस कडी में आप ने संगठन के मीडिया सह-सचिव देवाराम राठौङ मामबाक्कम प्रदेश उप-कोषाध्यक्ष कल्याणराम हाम्बङ पडवेङ;मनोरज ओमप्रकाश संदावासल प्रेम राठौङ वनाकुलम मोहनलाल गहलोत कनमंगलम, वैलूर जिला प्रभारी हिमताराम हाम्बङ; नेतीराम मुलेवा, जिला सचिव मुरली काटपाडी, काटपाडी क्षैत्रीय अध्यक्ष बागचंद जैन, राजेश कोठारी, गुडियातम इकाई के क्षेत्रीय अध्यक्ष सदाशिवम कोषाध्यक्ष सुनील जैन, और तमिलनाडु व्यापारी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवरलाल बाफना से चर्चा की। आप ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और व्यापारियों को अन्याय और पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ लडने का संकल्प दोहराया। माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय ने विश्वास दिलाया कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ व्यापार करने वाले हर व्यापारी के साथ संगठन मजबूती से उसके साथ खडा हैं। सभी पदाधिकारियों और व्यापारियों द्वारा माननीय प्रदेशाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। वैलूर जिले के जिला प्रभारी हिमताराम हाम्बङ द्वारा क्षैत्र में कुछ असामाजिक तत्वों और बदमाश प्रवृत्ति के लोगों द्वारा व्यापारियों से जबरदस्ती हफ्तावसूली करने और मना करने पर डराने धमकाने का मामला साझा किया। स्वामीजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों को ऐसे तथाकथित गुण्डों के खिलाफ ज्ञापन देने का भरोसा दिलाया। साथ ही पीडित व्यापारीयों को सलाह दी कि ऐसा मामला आते ही बिना झिझक और डर के संगठन पदाधिकारियों को बतायें। आप द्वारा संगठन की निःस्वार्थ सेवा भावना और मजबूत नेतृत्व के तले सभी व्यापारियों ने स्वामीजी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित किया।

नेहरू युवा केंद मुरैना ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई

केशव पडिंत जी अम्बाह

मुरैना। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र मुरैना के जिला युवा समन्वयक राकेश सिंह तोमर के निर्देशानुसार नेहरू युवा केंद्र संगठन पूरे जिले में सप्ताह भर तक गांधी जयंती पखवाड़ा मना रहा है। इसी क्रम में आज नेहरू युवा केंद संगठन ने श्री राघव युवा मंडल मुरैना, प्रथा संस्था, विकास क्रांति संगठन, विवेकानंद युवा मंडल, कायाकल्प युवा मंडल आदि युवा स्वयंसेवको के सहयोग से गाँधी कॉलोनी के गाँधी पार्क में गाँधी जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया । कार्यकम में नेहरू युवा केंद्र जिला युवा समन्वयक राकेश सिंह तोमर ने सभी युवा मंडलो के युवाओं के साथ बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर गांधीजी का भजन *वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे* का गायन किया फिर युवाओं को संबोधित करते हुए बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती नेहरु युवा केन्द्र संगठन पूरे जिले में मना रहा है।राकेश सिंह तोमर ने युवाओं से कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ओर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम विश्व के इतिहास में अमर है। इनकी उपलब्धियों एवं कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता। इन महापुरुषों द्वारा प्रज्ज्वलित दिव्य ज्योति आज भी हमारा मार्ग दर्शन कर रही है। आज पूरा विश्व महात्मा गांधी का अनुकरणीय बना हुआ है। उनके त्याग एवं बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। गांधीजी ने अपना पूरा जीवन धार्मिक आजादी की सुरक्षा, सम्मान देने, गरीबों तथा दबे-कुचले लोगों का उत्थान, अहिंसक विरोध तथा वार्ता के जरिये संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की खोज को समर्पित किया था। इस अवसर पर विशन सिंह तोमर, रामबिलास शर्मा, संदीप सेंगर, नितिन शिवहरे, रजनीश पंडित, मुरैना के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सचिन शिवहरे, सारिका बाथम, राहुल शर्मा, हिमांशु उपाध्याय, भोला पंडित, अनिकेत शर्मा, ब्रजेश शर्मा, विकास उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।

पुष्पांजली टुडे सामान्य ज्ञान

1. भारत नाम की उत्पति का सम्बंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है ?

(़) महाराणा प्रताप
(क्र) चन्द्रगुप्त मौर्या
(ष्ट) भरत चक्रवर्ती
(ष्ठ) अशोका मौर्या

2. भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है ?

(़) मुंबई
(क्र) कोलकाता
(ष्ट) दिल्ली
(ष्ठ) मद्रास

3. भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है ?

(़) उत्तर प्रदेश
(क्र) महाराष्ट
(ष्ट) राजस्थान
(ष्ठ) मध्यप्रदेश

4. भारत में कुल कितने राज्य है ?

(़) 28
(क्र) 29
(ष्ट) 36
(ष्ठ) 15

5. भारत का सबसे लम्बी नदी कौन है ?

(़) गण्डकी
(क्र) कोसी
(ष्ट) ब्रह्मपुत्र
(ष्ठ) गंगा

6. भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है ?

(़) ब्रह्मपुत्र
(क्र) गोमती
(ष्ट) गंगा
(ष्ठ) चम्बल

7. भारत का सबसे ऊँची मीनार कौन है ?

(़) चारमीनार
(क्र) कुतुब मीनार
(ष्ट) झूलता मीनारा
(ष्ठ) शहीद मीनार

8. भारत का सबसे लम्बा बाँध कौन सा है ?

(़) भाखड़ा बांध
(क्र) इंदिरा सागर बांध
(ष्ट) हीराकुण्ड बाँध
(ष्ठ) नागार्जुन सागर बाँध

9. भारत का सबसे लम्बी सुरंग है ?

(़) रोहतांग सुरंग
(क्र) जवाहर सुरंग
(ष्ट) मलीगुड़ा सुरंग
(ष्ठ) कामशेट सुरंग

10. भारत का सबसे ऊँची मूर्ति है ?

(़) हरमंदिर साहिब
(क्र) हाम्पी
(ष्ट) नालंदा
(ष्ठ) गोमतेश्वर

11. भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ?

(़) 1917
(क्र) 1915
(ष्ट) 1916
(ष्ठ) 1925

12. भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है ?

(़) श्री पदमावती महिला विशवविद्यालय
(क्र) एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय
(ष्ट) वनस्थली विद्यापीठ
(ष्ठ) स्त्र्कमहिला विश्वविद्यालय

13. भारत का पहला राष्टपति ?

(़) पंडित जवाहर लाल नेहरू
(क्र) डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन
(ष्ट) डॉ0 राजेंद्र प्रसाद
(ष्ठ) इनमें से कोई नहीं

14. भारत का पहला उपराष्टपति ?

(़) जाकिर हुसैन
(क्र) डॉ0 एस0 राधाकृष्णन
(ष्ट) गोपाल स्वरूप पाठक
(ष्ठ) इनमें से कोई नहीं

15. भारत का पहला प्रधानमंत्री ?

(़) पंडित जवाहर लाल नेहरू
(क्र) सरदार बलदेव सिंह
(ष्ट) जनरल राजेंद्र सिंह जी
(ष्ठ) इनमें से कोई नहीं

16. भारत का पहला गृह मंत्री ?

(़) वल्लभभाई पटेल
(क्र) डॉ0 राजेंद्र प्रसाद
(ष्ट) जवाहरलाल नेहरू
(ष्ठ) जॉन मथाई

17. भारत का पहला रेल मंत्री ?

(़) लाल बहादूर शास्त्री
(क्र) ललित नारायण मिश्र
(ष्ट) बंसी लाल
(ष्ठ) जॉन मथाई

18. भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था ?

(़) सरदार पटेल
(क्र) महलनोबीस
(ष्ट) दादाभाई नौरोजी
(ष्ठ) वी. के. आर. वी. राव

19. किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है ?

(़) प्राकृतिक संसाधन
(क्र) बाजार का आकर
(ष्ट) पूंजी निर्माण
(ष्ठ) उपर्युक्त सभी

20. डब्ल्यू. टी. ओ. का मुख्यालय कहाँ है ?

(़) न्यूयॉर्क
(क्र) जेनेवा
(ष्ट) यूरुगे
(ष्ठ) दोहा

21. मुद्रा-आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है ?

(़) वित्त आयोग
(क्र) योजना आयोग
(ष्ट) व्यापारिक बैंक
(ष्ठ) भारतीय रिजर्व बैंक

22. भारत में सबसे ऊँचा जलप्रताप कौन-सा है ?

(़) होगेनक्कल प्रपात
(क्र) शिमला प्रपात
(ष्ट) जोग प्रपात
(ष्ठ) कोर्टाल्लम प्रपात

23. रुसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई ?

क (़) वर्ष 1916

क (क्र) वर्ष 1917

क (ष्ट) वर्ष 1918

क (ष्ठ) वर्ष 1919

24. यूनियन ऑफ़ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया ?

क (़) वर्ष 1920

क (क्र) वर्ष 1921

क (ष्ट) वर्ष 1922

क (ष्ठ) वर्ष 1923

25. वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया ?

क (़) एंगेल्स

क (क्र) कार्ल मार्क्स

क (ष्ट)़ व क्रदोनों

क (ष्ठ) इनमें से कोई नहीं

26. चीनी क्रांति का नायक कौन था ?

क (़) च्यांग काई शेक

किसान सम्मान निधि योजना किसानों को हर साल 6000 रुपये

दिल्ली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के दो हजार रुपये लाभार्थी किसानों के खातों में आने लगे हैं। इस योजना के तहत हर साल योग्य लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में केंद्र सरकार 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। छठी किस्त आने के बाद काफी किसान इस बात से परेशान है कि क्या वह इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं या नहीं? सरकार की इस योजना का फायदा उठाने के लिए उन्हें क्या करना होगा और क्या शर्तें पूरी होने पर वह पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहां हम आपको पीएम किसान योजना से जुड़े नियम और शर्तें बता रहे हैं।

आपके नाम होना चाहिए खेत: पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम खेती की जमीन होनी चाहिए। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम नहीं है, तो वह लाभार्थी नहीं होगा। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो भी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं उठा सकते।

इन किसानों को नहीं मिलता लाभ: अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलता। इसके अलावा प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार के लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिलता।

गरीब किसानों के लिए नया उजाला संबल योजना

कोरोन संकट के बीच महामारी से जूझ रहे लोगों की जिन्दगी में संबल देने वाली, सहारा देने वाली योजना संबल, गरीब जनता की जिंदगी में नये प्रकाश के रूप में आयी है। संबल केवल योजना नही है बल्कि गरीबों का सहारा है संबल, बच्चों का भविष्य है संबल, माँ, बहन, बेटियों का सशक्तिकरण है संबल। जीवन की कठिन लड़ाई में ऐसे गरीब भाई बहनों जो आर्थिक रूप से संपन्न नही है उन्हें सहारा चाहिए, साथ और सहयोग चाहिए। संबल योजना इसीलिए लागू की गई है। इस योजना के माध्यम से गरीबों को न्याय मिल रहा है, यही सामाजिक न्याय है। संबल योजना में पहले कार्ड बने थे। योजना शुरू होते ही सभी पंजीकृत हितग्राहियों को लाभ मिलने लगा। संबल योजना ऐसी है जो जन्म से जीवन पर्यन्त तक हितग्राहियों को लाभ पहुँचाती है। संबल योजना के पात्र बहन को बेटा, बेटी जन्म देने के पहले 4 हजार रूपये और जन्म देने के बाद 12 हजार रूपये उनके खाते में दिये जाते है। यह सहायता बहनों को आराम करने का अवसर देती है और पोषण आहार भी मिलता है। इस योजना में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों के मामा कहे जाते हैं। संबल में पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। किताबें, आठवीं तक यूनिफार्म् और मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था रहती है। मुख्यमंत्री ने एक नई योजना इसमें जोड़ी है, संबल परिवार के ऐसे बच्चे जो 12वीं में मेरिट में आते है ऐसे 5 हजार बच्चों को 30 हजार रूपये प्रति विद्यार्थी अलग से दिये जायेगें। संबल योजना में गरीबों को सस्ते दर पर बिजली तथा बीमारी के लिए सहायता भी दी जाती है। पंजीकृत व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रूपये की राशि परिवार के सहारे के लिए दी जाती है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रूपये, अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रूपये की व्यवस्था संबल में की जाती है। आंशिक स्थाई अपंगता पर भी आर्थक सहायता संबल के तहत मिलती है। संबल गरीब के लिए एक पूरा पैकेज है, ऐसी योजना देश में किसी भी राज्य में नही हैं।

ग्रामीण अंचल में वरदान साबित हुई पंच-परमेश्वर योजना

मध्यप्रदेश में 22 हजार 812 ग्राम पंचायतों और 55 हजार से अधिक गाँव वाले इस राज्य में 2 तिहाई आबादी गाँव में ही निवास करती है। इन परिस्थितियों, इतनी आबादी और पंचायत राज संस्थाओं को सक्रिय बनाना एक बड़ी चुनौती थी। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 (नियंत्रित करने) के लिए बहु-आयामी रणनीति पर काम किया गया। इसका परिणाम है कि मध्यप्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में कोरोना मरीजों की संख्या कम रही है।

ग्रामीण अंचल में कोरोना से लड़ने तथा पंचायतों के सुदृढ़ीकरण में पंच-परमेश्वर योजना वरदान साबित हुई है। 10 जून को 14वें वित्त आयोग की 1555 करोड़ रूपये की राशि ग्राम पंचायतों को जारी की। इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ राशि मिलने से ग्राम-पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। प्रदेश में औसतन 7 से 8 लाख रूपये की राशि एक ग्राम-पंचायत के खाते में पहुँची है। राज्य सरकार ने पंच-परमेश्वर% योजना की गाइडलाइन में भी ग्राम-पंचायतों को अधिक स्वतंत्रता और स्वायत्ता दी। कोरोना संक्रमण के इस दौर में ग्राम-पंचायतों के सामने मुख्य चुनौती थी गाँव

और ग्रामीणों को कोरोना के संक्रमण से बचाना, गाँव में स्वच्छ पेयजल और अधोसंरचना को सुदृढ़ करना। पंच-परमेश्वर योजना 14वें वित्त की राशि में 2.5 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत के सेनिटाईजेशन, ग्रामीणों और प्रवासी मजदूरों को मास्क उपलब्ध कराने पर व्यय की अनुमति दी गई। ग्राम-पंचायतों में अधोसंरचना विकास के सारे काम पुनः शुरू हो चुके हैं जो स्थानीय रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। 20 अप्रैल को भारत सरकार द्वारा मनरेगा से जुड़े रोजगार पुनः प्रारम्भ करने की गाइड लाइन जारी की गई। प्रदेश में 73 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी किये गये हैं। इनमें 29 जून को 20 लाख 65 हजार श्रमिकों को 7 लाख 79 हजार कार्यों में रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में 1861 करोड़ रूपये की राशि मजदूरी के रूप में तथा 616 करोड़ रूपये की राशि निर्माण सामग्री के रूप में भुगतान की गई है। प्रदेश में लौटकर आए प्रवासी मजदूरों को नवीन जॉब कार्ड मुहैया कराने के लिए श्रम सिद्धि योजना प्रारंभ की गई, अभी तक 3 लाख 65 हजार श्रमिकों के नवीन जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं।

डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है नीट परीक्षा, ऐसे करें इसकी तैयारी

नीट परीक्षा की योग्यता की बात करें तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 50 परसेंट मार्क होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक की कम से कम 17 वर्ष की उम्र होना चाहिए। नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट! यह परीक्षा देशभर में मेडिकल कॉलेजेज में एडमिशन लेने के लिए आयोजित की जाती है। 12वीं के बाद अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और इससे संबंधित एमबीबीएस अथवा बीडीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप को इस नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इस परीक्षा की योग्यता की बात करें तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ मिनिमम 50 परसेंट मार्क होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक की कम से कम 17 वर्ष की उम्र होना चाहिए। जान लें कि अगर आपने 12वीं की पढ़ाई ठीक ढंग से की है, खासकर बायोलॉजी, फिजिक्स व केमिस्ट्री में, तो आप इस परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं, किंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली एकमात्र मेडिकल परीक्षा है। अतः कंपटीशन बेहद

कठोर होता है। अतः मुश्किल तो होगी, किन्तु यह नामुमकिन कतई नहीं है! परीक्षा के माध्यम की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी में इसके प्रश्न दिए जाते हैं। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो ऑनलाइन इसकी काउंसलिंग होती है और नेशनल लेवल के अलावा स्टेट लेवल पर भी इसकी काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है। इसमें अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से सीटों को आवंटित किया जाता है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर इसकी दूसरी कई जानकारियां आपको मिल जाएंगी। यहां तक कि आप मॉक टेस्ट का पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। कॅरियर एक्सपर्ट्स तैयारी के लिए सलाह देते हैं कि आपको काफी पहले से इस पर ध्यान देना होता है, किंतु जिस स्तर का टफ एग्जामिनेशन होता है, उसे देखते हुए आपको अंतिम के तकरीबन 2 महीने बेहद सटीकता से रिवीजन पर बिताना होगा। इसके लिए आपको न केवल स्ट्रेस से बचना होगा, बल्कि बेहतरीन तैयारी के लिए पूरी शेड्यूलिंग करके अलग-अलग सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। ध्यान रहे! यह कोई साधारण एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए आप भिन्न एक्सपर्ट्स से मार्गदर्शन लेने में संकोच ना करें। अंत में आपको संपूर्ण सिलेबस पर ध्यान देना होता है और सिलेक्टिव टॉपिक्स को स्टडी करने से बचना है। आपको सम्पूर्ण कोर्स के अधिक से अधिक हिस्सों को, कम से कम समय में कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रहे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि कड़ी मेहनत ही आपको इसमें इक्षित परिणाम दे सकती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले फिलहाल क्या करें?

व्यायाम के माध्यम से खुद को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर इस वक्त आप कम्युनिटी में खेल भी नहीं सकते, इसलिए यह और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी दिनचर्या को नियमित रखते हुए तन को स्वस्थ रखा जाए। ऐसे लाखों बच्चे होंगे जो मन में सपने सजाये होंगे कि 12वीं के बाद वह किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल संस्थान में दाखिला लेंगे और कॅरियर के पड़ाव में अगला कदम रखेंगे। मुसीबत यह है कि कोविड-19 के काल ने हर एक की योजनाओं पर कुठाराघात कर दिया है। सबसे मुश्किल उन बच्चों के सामने है, जिन्होंने 12वीं का एग्जाम देकर सुनहरे कॅरियर के सपने संजोए थे। इस समय वह किंमकर्तव्यविमूढ़ हो गए हैं।

तन और मन को रखें स्वस्थ

जी हां! किसी भी प्रकार की चिंता करने की बजाय आपको खुद को स्वस्थ रखना कहीं ज्यादा आवश्यक है। आगे क्या होगा, कौन सा कॅरियर आप चुनेंगे, इसको लेकर बेवजह का तनाव आपको नहीं लेना चाहिए। बल्कि, इसकी बजाय आपको जितना संभव हो व्यायाम के माध्यम से खुद को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के नाम पर इस वक्त आप कम्युनिटी में खेल भी नहीं सकते, इसलिए यह और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी दिनचर्या को नियमित रखते हुए तन को स्वस्थ रखा जाए। इसी प्रकार यह अवस्था ऐसी है कि मन भटकाव के दौर में गुजरता है, इसलिए हर किसी के घर

में गीता रामायण जैसी किताबें भी होती हैं, उसका अध्ययन करके आप अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयत्न करें। ऑनलाइन भी कई सारी बुक्स उपलब्ध हैं, यहां तक कि ऑडियो और वीडियो बुक्स का भी आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन आवश्यक है कि तन और मन को पूरी तरह से स्वस्थ रखा जाए।

जल्दबाजी में ना करें ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने का फैसला

कई बार बच्चे जल्दबाजी में तमाम कोर्सेज में एडमिशन लेने का फैसला कर बैठते हैं। वर्तमान में कई सारी कोचिंग संस्थाएं और दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ट्रेनिंग और कोचिंग देने के नाम पर भारी-भरकम फीस वसूलने लगे हैं, पर विडंबना यह है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की उनके पास खुद बेसिक सुविधाएं नहीं हैं। कइयों के पास, उनके शिक्षक ऑनलाइन ट्रेनिंग देने में और काउंसलिंग करने में दक्ष ही नहीं हैं, और ना ही उनके पास इससे संबंधित बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसे में अगर आप जल्दबाजी में किसी इंस्टिट्यूट के ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने का फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में आपको निराशा हाथ लगेगी। इसकी बजाय आवश्यक है कि इंटरनेट पर पहले सम्बंधित संस्थान का फ्री डेमो देखने का प्रयत्न करें और फ्री डेमो से अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो पार्टिकुलर संस्थान के बारे में रिव्यू देखें। इसके बाद आप प्राइस कंपैरिजन करके किसी निश्चित कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। लेकिन यह समझना आवश्यक है कि दाखिला लेने के पश्चात आप उपयुक्त कोर्स का कितना यूटिलाइजेशन कर सकेंगे, सिर्फ एडमिशन लेने के लिए पैसे और समय की बर्बादी न करें, बल्कि उसका उपयोगी होना सुनिश्चित करें विशेषज्ञों के अनुसार, अगर आप ध्यान रखकर फैसला लेते हैं तो उसका बेहतर उपयोग आप आसानी से सुनिश्चित कर सकेंगे।

एक बेंचमार्क क्रिएट कर चुकी हैं विद्या

दमदार अभिनय के लिए चार बार फिल्मफेयर अवार्ड से नवाज़ी जा चुकी विद्या बालन, मजबूत किरदारों और शानदार एक्टिंग से इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसों को कड़ी टक्कर देती रही हैं.'परिणीता' (2005) से अपने कैरियर की शुरूआत करने के बाद विद्या बालन ने 'गुरू' (2007), 'पा' (2009), 'इश्किया' (2010) 'द डर्टी पिक्चर' (2011) 'कहानी' (2012) और 'तुम्हारी सुलु' (2017) जैसी महिला आधारित फिल्मों में जबर्दस्त प्रभाव पैदा किया. इन फिल्मों की कामयाबी ने साबित कर दिया कि अपने बलबूते पर फिल्म को हिट करवाने की पूरी काबिलियत विद्या के पास है.'शकुंतला देवी' में विद्या बालन ने महान गणितज्ञ शकुंतला देवी का किरदार निभाया.

बंगला फिल्म जगत के लोकप्रिय अभिनेता जीशु सेन गुप्ता ने फिल्म में शकुंतला देवी के पति का किरदार निभाया.विद्या बालन का कहना है कि वह बचपन से गणित में बेहद कमजोर रही हैं. गणित का नाम आते ही उन्हें सांप सूंघ जाया करता था. वह हमेशा इससे बचकर निकल जाने की फिराक में रहती थी. ऐसे में जब उन्हें अनु मेनन की ओर से 'शकुंतला देवी' की बायोपिक में शीर्षक भूमिका निभाने का प्रस्ताव मिला तब उन्हें काफी आश्चर्य हुआ था. विद्या बालन का मानना है कि वह 'शकुंतला देवी' के पहले कुछ बायोपिक कर चुकी थी हो सकता है कि इसी वजह से अनु के दिल में इस किरदार के लिए उन्हें लेने का ख्याल आया हो. एक बार जब उन्होंने ऑफर स्वीकार किया तो किरदार को संजीदगी के साथ निभाने के लिए कोई कसर नहीं रहने दी. विद्या बालन को इस बात का बेहद मलाल है कि 'शकुंतला देवी' को थियेटर के दर्शकों के लिए बनाया गया था, लेकिन लंबे लॉक डाउन और देश भर के थियेटर अनिश्चित काल के लिए बंद होने की दशा में फिल्म के मेकर को इसे ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला लेना पड़ा. अपने कैरियर के साथ ही साथ विद्या बालन सामाजिक गतिविधियों में भी हमेशा आगे रही हैं. उन्होंने लॉक डॉउन के दौरान मुंबई के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1000 पीपीई किट उपलब्ध करवाई. विद्या का मानना है कि इस मुश्किल घड़ी ने हमें, आत्म निर्भर होना सिखाया. इन दिनों विद्या बालन, 'मर्डर 3' और 'न्यूटन' जैसी फिल्में बना चुके अमित मुसरकर के निर्देशन में बन रही 'शेरनी' कर रही हैं. इसमें वो एक फोरेस्ट ऑफीसर के किरदार में नजर आएंगी. फिल्म को भूषण कुमार प्रोडयूस कर रहे हैं. अत्याचार के मुद्दे पर आधारित एक शार्ट फिल्म भी विद्या बालन ने की है, इसमें रेप को समाज की सच्चाई के तौर पर प्रस्तुत किया गया है . इस शार्ट फिल्म का प्रदर्शन इंटरनेशल फिल्म

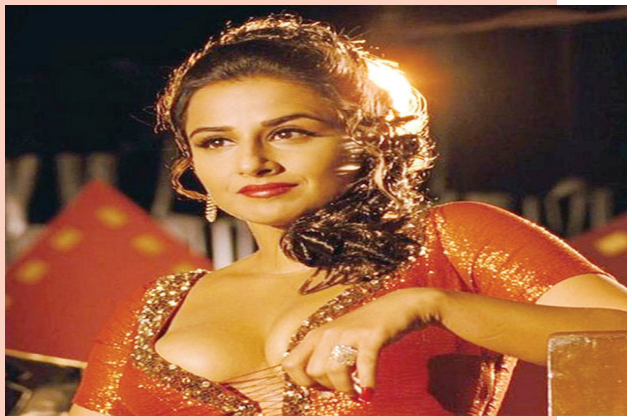

फेस्टिबल में किया जा चुका है. शार्ट फिल्म के इस किरदार को निभाते वक्त विद्या बालन एकदम ग्रामीण परिवेश की किसी महिला की तरह नजर आई और यकीनन इस तरह की खूबी उबरती है, सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस की एक्टिंग के जरिए. इस तरह की खूबी कभी नूतन, स्मिता पाटिल और शबाना आजमी की एक्टिंग में नजर आती थी.हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक, अनेक महान अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग टेलेंट से ऑडियंस के दिलो दिमाग में एक मायाजाल सा रच दिया था. विद्या बालन भी उन्हीं में से एक आज के दौर की एक्ट्रेस हैं. शुरू से विद्या बालन की कोशिश यही रही है कि वह जब कोई किरदार निभाती हैं तो पूरी तरह उसका हिस्सा बन जाती है. शायद यही वजह रही कि उनका अनावश्यक बढ़ता वजन और शेप से बाहर जाता शरीर कभी उनके काम में बाधा नहीं बन सका.